A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 29 जुलाई, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 327, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मैंने लिखा
एक अंकुर
वह पेड़ हो गया

मैंने लिखा
एक शब्द
वह महाकाव्य
हो गया

मैंने लिखा
धूल का एक कण
वह सारी
दुनिया हो गया

मैंने लिखा
एक फूल
सारी सृष्टि सुगंधित
हो गई

मैंने लिखा
जल की एक बूंद
वह महानदी बन गया।
-दुर्गाप्रसाद झाला

प्रसंगवश

फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या वाकई तेजी से मामले निपटा पाते हैं

इमरान क़ुरैशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार को यह आश्वासन दिया है कि नीट पेपर लीक के कथित अभियुक्तों के मुक़दमों की सुनवाई के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था पिछले लगभग ढाई दशकों से मौजूद है। लेकिन इन्हें गति तब मिली, जब जब जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए ऐसी अदालतें बनाने की सिफ़ारिश की थी।

इसके बावजूद, इन अदालतों में न्याय की प्रक्रिया हमेशा इतनी तेज़ नहीं रही कि पीड़ितों या उनके परिवारों को समय पर राहत मिल सके। कई मामलों में सुनवाई लंबी खिंचती रही। नतीजा यह हुआ कि अभियुक्तों को ज़मानत मिल गई और मामले वर्षों तक लटके रहे। कई मामलों में इनकी स्थिति नियमित अदालतों से अलग नहीं रही है।

गुरुवार रात प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को कुछ विशेषज्ञ महज़ एक 'बैंडेज' यानी अस्थायी उपाय बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।

उनकी दलीलों को फ़ास्ट ट्रैक अदालतों के कामकाज पर हुए विस्तृत अध्ययनों का समर्थन मिलता है। इन अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई में भी अक्सर देरी होती है, जो सिर्फ महिलाओं और बच्चों ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को गहरे सदमे और परेशानी में डाल देते हैं।

क़ानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट और सामान्य अदालतों के कामकाज में कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। इस बारे में विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी के सह-संस्थापक और वकील आलोक प्रसन्न कुमार ने कहा, 'फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट और सामान्य अदालत में कोई अंतर नहीं है। जजों की कमी यहां भी दिखाई देती है, वही वकील और वही व्यवस्था होती है। सिर्फ अदालत को एक नया नाम देकर उसे फास्ट कोर्ट घोषित कर दिया जाता है। 'मान लीजिए अदालत इस मामले को प्राथमिकता देकर सुनवाई शुरू भी कर दे, तब भी औसतन फ़ैसला आने में साढ़े तीन से चार साल लग सकते हैं। पेपर लीक का यह मामला मामला नहीं है जिसे बहुत जल्दी निपटाया जा सके।'

बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर अपर्णा चंद्रा ने इससे समस्या की जड़ दूर नहीं होती। बुनियादी ढांचे की कमी, कर्मचारियों का टोटा और काम का भारी बोझ जैसी समस्याएं कायम हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर ने कहा, 'मैंने फ़ास्ट-ट्रैक अदालतों के कामकाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि मौजूदा जजों को ही फ़ास्ट-ट्रैक अदालतों की ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। इसके लिए अलग से अतिरिक्त जजों की नियुक्ति नहीं की जाती। इस कारण ये अदालतें भी पुराने मामलों के बोझ तले दब जाती हैं। इसलिए यह व्यवस्था वास्तव में पुरानी प्रणाली का ही विस्तार बनकर रह जाती है।'

विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी की ओर से 2017-18 में किए गए दो अध्ययनों से इसे समर्थन भी मिलता है। इसके पाँच साल बाद वर्ष 2022-23 में एक और अध्ययन किया गया। यह अध्ययन विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी की 'जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज़ इन इंडिया' पहल और विश्व बैंक के डेटा एविडेंस फ़ॉर जस्टिस रिफ़ॉर्म कार्यक्रम के सहयोग से किया गया था। दूसरे अध्ययन में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग चार लाख पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण क़ा डेटा जुटाया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, फ़ास्ट-ट्रैक अदालतों में केवल 22 फ़ीसदी मामलों का ही निपटारा हो पाया। सिर्फ़ 22 फ़ीसदी मामलों का फ़ैसला एक साल से कम समय में हुआ।

करीब 42 फ़ीसदी मामलों में सुनवाई पूरी होने में तीन साल से ज़्यादा समय लगा वहीं 17 फ़ीसदी मामलों में पाँच साल से भी अधिक समय लग गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिकांश मामलों का निपटारा एक साल के भीतर हो गया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसे मामले निपटाने में तीन साल लगे। हालांकि 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने वाला दूसरा अध्ययन कहीं ज्यादा व्यापक था। इसमें लगभग चार लाख पॉक्सो मामलों को शामि ल किया गया था, जिनमें से 2,30,730 मामलों का मेटाडेटा विश्लेषण किया गया। उत्तर प्रदेश में लंबित मामलों की संख्या सबसे ज़्यादा थी वहाँ 2012 से फ़रवरी 2021 के बीच दर्ज़ पॉक्सो मामलों में तीन चौथाई से अधिक केस लंबित थे।

चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में मामलों के निपटारे का औसत समय लगभग एक साल रहा। बाकी अधिकांश राज्यों में सुनवाई में इससे अधिक समय लगा। केरल एकमात्र ऐसा राज्य था, जहाँ दोषसिद्धि और दोषमुक्ति के मामलों के बीच का अंतर सिर्फ़ 20.5 फ़ीसदी था। 2023 की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए। इनमें पॉक्सो मामलों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और पर्याप्त संख्या में विशेष लोक अभियोजकों (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) की नियुक्ति की सिफारिश भी शामिल थी।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि जांच और आरोप-पत्र दाखिल करने में काफ़ी देरी होती है इसकी एक प्रमुख वजह पुलिस जांच की धीमी रफ़्तार है, जिससे मामलों का लंबित बोझ बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक़, फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफ़एसएल) में नमूने जमा कराने में होने वाली देरी के कारण समस्या और गंभीर हो जाती है।

प्रोफ़ेसर अपर्णा चंद्रा का कहना है कि न्यायाधीश अकेले काम नहीं करते। उन्हें अच्छी जांच, मज़बूत अभियोजन और प्रभावी बचाव पक्ष की भी ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा, 'सिर्फ़ फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बना देने से ये सारी चीज़ें अपने-आप सुनिश्चित नहीं हो जाती। ट्रैक अदालत किसी मामले का फैसला दो तीन माह में कर भी दे तो तब भी मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जहां पहले ही काम का बहुत बोझ है। इससे मुकदमे में और समय लगेगा।

प्रोफ़ेसर चंद्रा ने कहा, 'अगर सरकार और व्यवस्था वास्तव में फ़ास्ट-ट्रैक अदालतों को लेकर गंभीर है, तो अतिरिक्त जजों की नियुक्ति करनी होगी, इन जजों को केवल ऐसे ही मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी देनी होगी। साथ ही ऐसे मामलों को दूसरी अदालतों में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

इसके साथ साथ वकीलों का सहयोग भी जरूरी है। जो वकील दूसरे मुकदमों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें भी सहयोग करना होगा ताकि फास्ट ट्रैक अदालतें मामलों का निपटारा जल्द कर सकें।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

नए एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ राफेल की होगी और तेज डिलीवरी

- डसॉल्ट के पास 208 विमानों का ऑर्डर, नए 'एंटी-ड्रोन' सिस्टम से होगा लैस

पेरिस (एजेंसी)। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने 2026 की पहली छमाही में 12 राफेल लड़ाकू विमान सौंप दिए हैं और साल खत्म होने से पहले 16 और विमान सौंपने की योजना है। इस शेड्यूल के हिसाब से फ्रांसीसी कंपनी 2025 में सौंपे गए 26 राफेल विमानों की संख्या को पार कर जाएगी। पहली छमाही में सौंपे गए विमानों में से दो फ्रांस को दिए गए जबकि 10 विमान एक्सपोर्ट ग्राहकों को सप्लाई किए गए। डसॉल्ट ने विदेशी ग्राहकों के नाम नहीं बताए। जून के आखिर में कंपनी के पास राफेल के 208 विमानों के ऑर्डर पेंडिंग थे। इससे प्रोडक्शन का एक बड़ा आधार मिलता है क्योंकि डसॉल्ट फ्रांस और विदेशी ग्राहकों को लगातार विमान सौंप रहा है। साल के अंत से पहले ऑर्डर बुक में और विस्तार हो सकता है। जुलाई में यूक्रेन ने 16 राफेल खरीदने के लिए फ्रांस सरकार से एक समझौता किया था। भारत भी 114 राफेल विमानों के संभावित ऑर्डर पर फ्रांस से बात कर रहा है। इसके अलावा इराक ने अलग से राफेल में दिलचस्पी जताई है।

सुप्रीम आदेश, तुरंत रिहा किए जाएं नाबालिग प्रदर्शनकारी

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था

कहा- जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई हो

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले दिए गए दिशा-निर्देशों को अब अपडेट करने का समय आ गया है। 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।

- **छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है-** सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस, दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी।
- **कई राज्यों को नोटिस-** दूसरे राज्यों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। इसलिए राज्यों को नोटिस भेजे हैं।

सुनवाई खत्म अगली तारीख 3 अगस्त तय

सुनवाई के आखिर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जुनैद मलिक की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की मांग का विरोध किया। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पहले याचिका की सभी तकनीकी कमियां दूर की जाएं। इसी दौरान एक वकील ने अपनी याचिका भी सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा कि हिरासत में लिए गए छात्रों की मदद के दौरान उन पर भी हमला हुआ था। बेंच ने कहा कि इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी, जबकि बाकी मामलों में तीन को।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए कई निर्णय

सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2 हजार 480 करोड़ रूपये की मंजूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण को गति देने के लिए लगभग 2 हजार 480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई। बैठक में खेल गतिविधियों, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई।

प्रमुख निर्णयों में अक्टूबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी के भव्य आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य की खेल अवसंरचना और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए रिहन्द एवं मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं और किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को मंजूरी मिली। प्रदेश को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के उद्देश्य से आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आईटी पार्कों के विकास के लिए 857 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इन निर्णय में आई टी पार्क की स्थापना के वर्ष 2031 तक संचालन की निरंतरता की स्वीकृति महत्वपूर्ण है, इसके तहत करीब 8000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए 198 करोड़ रुपये, कर्मचारी कल्याण एवं पेंशन योजनाओं के लिए 982 करोड़ रुपये और ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा के निरीक्षकालय के नवीन वृत्त कार्यालय और नारायणगढ़ में 9 नए न्यायिक पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

मेटा ने पहले मोदी का वीडियो हटाया, अब रीस्टोर किया

- कहा-तकनीकी गड़बड़ी से हटा, पीएम ने छात्रों को मैसेज दिया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो मेटा ने दोबारा रीस्टोर कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया था। इससे पहले कुछ समय के लिए फेसबुक पर यह वीडियो दिखाई नहीं दे

रहा था, जिसके बाद इस पर सवाल उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो 23 जुलाई को जारी किया था। इसमें उन्होंने जेन-जी और छात्रों को संबोधित करते हुए परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। इधर, न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) के ग्लोबल हेड और कंपनी के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को भी तलब किया है।

23 जुलाई को पीएम ने वीडियो मैसेज पोस्ट किया था- 23 जुलाई की रात 12 बजे एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए 2.56 मिनट के वीडियो मैसेज में मोदी ने कहा- पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक कई कदम उठाए हैं।

गुरु पूर्णिमा: आज पूरे प्रदेश में मनेगा महर्षि सांदीपनि गुरू पर्व

श्रीराम तिवारी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में इस वर्ष गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई) को पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनि गुरू पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में गुरु-पूजन, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम, छात्र-शिक्षक संवाद तथा भारतीय गुरु-शिष्य परम्परा पर आधारित विविध गतिविधियाँ आयोजित होंगी। इसी मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका आयोजन श्रीकृष्ण पाथेय न्यास द्वारा किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जित 14 विधाओं, 64 कलाओं, महर्षि सांदीपनि तथा भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित होगी। योजना अंतर्गत अंतर्गत 102 मेधावी छात्र-छात्राओं को रू. 1 लाख की एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के माध्यम से विजेता विद्यार्थियों का चयन लॉटरी के द्वारा किया जायेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीराम तिवारी ने दी।

श्रीराम तिवारी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व केवल उनकी लीलाओं और पराक्रम से नहीं, बल्कि महर्षि सांदीपनि के आश्रम में प्राप्त शिक्षा, संस्कार और अनुशासन से पूर्ण हुआ। वहीं उन्होंने 14 विद्याओं, 64 कलाओं तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से विवेक, सेवा, धैर्य, कर्तव्य, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व का पाठ सीखा। यही गुरु शिष्य परंपरा उनके जीवन की सबसे बडी शक्ति बनी और आगे चलकर उन्हें जगद्गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। आज आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परम्परा, संस्कारों और गुरुजनों के प्रति सम्मान से पुनः जोड़ा जाए।

इसी उद्देश्य से श्रीकृष्ण पाथेय न्यास द्वारा भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के 51 विद्यार्थी विद्यालय से एवं 51 विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से चयन होंगे। जिन्हें श्रीकृष्ण पाथेय न्यास द्वारा राशि रूपये रू. 1 लाख की एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जित 14 विद्याओं, 64 कलाओं, महर्षि सांदीपनि तथा भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित होगी।

तिवारी ने बताया कि गुरूपूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय गुरू परंपरा के शिल्पी महर्षि सांदीपनि, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा प्रकाशित महर्षि सान्दीपनि श्रीकृष्ण विद्यांजलि तथा जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक सर्वांग का लोकार्पण भी होगा। इसके साथ ही महर्षि सांदीपनि के जीवन पर केन्द्रित एक ई-बुकलेट प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करायी जा रही है।

राष्ट्र में नव जागरण तथा उत्कर्ष के लिये भारत वर्ष और विश्व के पथ प्रदर्शक, युगावतार भगवान श्रीकृष्ण द्वारा उज्जैन, मध्यप्रदेश को केन्द्र में रख कर की गई यात्रा के विभिन्न स्थलों के पुरान्वेषण तथा उन्हें तीर्थ के रुप में विकसित करने तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के साहित्य, संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता एवं माननीय संस्कृति मंत्रीजी की उपाध्यक्षता में मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की स्थापना की गयी। इसके उद्देश्यों में मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण की यात्राओं से जुड़े स्थलों की पहचान, विकास, संरक्षण तथा उनका अभिलेखन, फोटोग्राफी, फिल्मांकन एवं चित्रांकन।

इन स्थलों के मंदिरों, जल संरचनाओं, वन संपदा एवं उद्यानों का संरक्षण तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार। उज्जैन में 14 विद्याओं एवं 64 कलाओं की औपचारिक शिक्षा हेतु सांदीपनि गुरुकुल की स्थापना। सभागार, सामुदायिक भवन तथा धर्मशालाओं का निर्माण एवं संचालन। शिक्षा, संस्कृति, कृषि तथा गौ एवं पशुधन पालन की विरासत का विकास। नई पीढ़ी को भगवान श्रीकृष्ण की कथा एवं यात्रा स्थलों से भावनात्मक तथा अनुभवात्मक रूप से जोड़ना। पर्यटकों, शोधार्थियों, युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, संग्रहालय तथा सूचना केंद्रों की स्थापना। साथ ही उन ऋषियों, संतों, विचारकों, कवियों, लेखकों, कलाकारों एवं वैज्ञानिकों के योगदान का अभिलेखन जिन्होंने श्रीकृष्ण को जगद्गुरु के रूप में स्थापित किया, शामिल है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 29 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

बकायन गांव : गुरु पूर्णिमा का दिन संगीत-साधना का पर्व

गुरु पुर्णिमा विशेष

राजेन्द्र शर्मा

लेखक स्तंभकार हैं।

भारतीय शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परम्परा का बहुत बड़ा स्थान है। देश का सबसे प्राचीनतम संगीत समारोह जालंधर में हरिबल्लभ संगीत समारोह 150 वर्षों से संत एवं संगीताचार्य बाबा हरिबल्लभ की स्मृति में आयोजित होता है। हरिबल्लभ संगीत समारोह के बाद दूसरा सबसे प्राचीनतम संगीत समारोह के रुप में 'गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव' का नाम आता है। यह संगीत महोत्सव भी गुरु शिष्य परम्परा के तहत मृदंगाचार्य पंडित नाना साहेब पानसे की स्मृति में 131 वर्षों से अनवरत आयोजित हो रहा है। चौकाने वाली बात है कि गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह किसी महानगर,शहर में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जिले दमोह के एक छोटे से गांव बकायन में आयोजित होता है।

दो दिवसीय गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव प्रत्येक वर्ष बिना किसी व्यवधान के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहा है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां लगातार लगभग 48 घंटे तक संगीत की अविरल धारा बहती है। यह समारोह भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा, साधना, श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्तराधिकार का जीवंत उत्सव है।

पखावज वादन की महान परंपरा से जुड़े नाना साहेब पानसे का भारतीय ताल-संगीत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नाना साहेब पानसे की स्मृति में साल 1894 से आयोजित होने वाले इस समारोह के प्रारम्भ होने के बारे में जानकार बताते है कि सन् 1730 में महाराजा छत्रसाल मुगलों द्वारा घेर लिए जाने पर उन्होंने मदद के लिए बाजीराव पेशवा से गुहार लगाई। बाजीराव पेशवा ने महाराजा छत्रसाल की मदद कर मुगलों के चंगुल से बचाया और इस मदद का सम्मान करते हुए महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपनी संपत्ति का तीसरा हिस्सा बतौर तोहफा दे दिया ।

बाजीराव पेशवा को मिले इस तीसरे हिस्से से ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तार जुड़े माने जाते है। गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति के संरक्षक अरुण पलनीटकर, जो सिद्धहस्त सितारवादक हैं और उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी के निदेशक रह चुके है, बताते हैं कि जब महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपनी संपत्ति का तीसरा हिस्सा दिया था तो बाजीराव पेशवा ने अपनी सैनिकों को जागीरदारियां देकर उन्हें बुंदेलखंड में बसाया। अरुण पलनीटकर के परिवार के पूर्वज बाजीराव पेशवा की सेना में सैनिक थे। इस नाते उन्हें 5 गांवों बकायन, लुकायन, सकतपुर, भटेरा तथा अहरोरा की जागीरदारी मिली थी।

पांच गांव के जागीरदार पलनीटकर परिवार की तीसरी पीढ़ी के वंशज बाबू बालकृष्ण राव पलनीटकर जोकि बनारस में रहते थे । उन्होंने अपने दोनों बेटों माधवराव एवं छोटे बेटे बलवंत राव को जागीरदारी संभालने के लिए बकायन भेज दिया । बकायन आने के बाद बड़े बेटे माधव राव अंग्रेजी शासन काल में वन विभाग में रेंजर बन गए लेकिन कुछ समय बाद उनकी एक अफसर से खटपट हो गई और उन्होंने अंग्रेज अफसर को जवाब दे दिया। जिससे भिननाये अंग्रेज अफसर ने माधव राव को गोली मार दी।

अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज अफसर से टकराने से पूरा परिवार सहमा हुआ था। अंग्रेज अफसर की गोली से मारे गये माधवराव के छोटे भाई बलवंत राव भाई में ऐसा डर बैठ गया कि अंग्रेज अफसर पूरे परिवार को भी कहीं जान से न मार दें। इस डर से वह पूरे परिवार को भूमिगत करके स्वयं इंदौर चले गए और अग्रेंज अफसर उन्हेंद पहचान न सकें, इसके लिए बलवंत राव टोपीवाला के नाम से रहने लगे।

उस समय इंदौर में शिवाजी राव होलकर का शासन था। देश के प्रख्यात मृदंगाचार्य नानासाहेब पानसे उनके दरबार में राज दरबारी थे। बालकृष्ण राव टोपीवाला शास्त्री य संगीत के रसिक थे। उन्होंने नानासाहेब से कई बार विनती की कि उन्हें अपना शिष्य बना ले लेकिन शास्त्रीय संगीत की परम्परा में किसी साधक के लिए योग्य गुरु ढूंढना जितना दुरुह कार्य है, उतना ही दुरुह कार्य उस गुरु के द्वारा शिष्य बनाये की स्वीकृति प्राप्त करना। मृदंगाचार्य नानासाहेब पानसे ने बालकृष्ण राव टोपीवाला की विनती को अस्वीकार कर दिया।

बालकृष्ण राव टोपीवाला ने हार नही मानी। वह तीन साल तक नानासाहेब पानसे के रथ के आगे दौड़ते हुए हरकारे का काम करते रहे । संगीत की प्रति बालकृष्ण राव टोपीवाला की निष्ठा और समर्पण देखना नासाहेब पानसे को दिल पसीजा और उन्होंने बलवंत राव टोपीवाला को अपना शिष्य बना लिया।

तेरह वर्षों तक बालकृष्ण राव टोपीवाला अपने गुरु मृदंगाचार्य नानासाहेब पानसे से संगीत की तालिम लेते रहे। नाना साहेब से संगीत और मृदंग वादन की शिक्षा लेने के बाद बलवंत राव ऊर्फ बालकृष्ण राव टोपीवाला हालात कुछ बेहतर होने पर बकायन गांव वापिस पहुंचें ।

गांव बकायन लौटने पर बलवंत राव पांच गांवों के जागीरदार जरुर थे किन्तु उनका मन शास्त्रीय संगीत में रम चुका था। वह दिन भर शास्त्रीय संगीत के रियाज और अपने

शिष्यों को प्रशिक्षित करने में लगे रहते। बलवंत राव ने 57 लोगों को दीक्षित कर अपना शिष्य बनाया।

सन् 1891 में नाना साहेब पानसे के निधन के बाद अपने गुरु की स्मृति में बलवंत राव ने 1894 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत-साधना को सामूहिक रूप देने का निर्णय लिया। उस समय यह नियम बनाया गया था कि लगातार 48 घंटे तक एक ही बंदिश और राग को लगातार गाया या बजाया जाएगा। इसमें तमाम शिष्य और ग्रामीण भाग लेते थे। इस तरह यह क्रम चलता रहा लेकिन साल 1915 में बलवंत राव का निधन हो गया । बलवंत राव के निधन के बाद उनके बड़े भाई माधव राव के दत्तक पुत्र बेटे केशव राव ने अपने चाचा द्वारा स्थापित 21 साल पुरानी परम्परा को संजोने का निर्णय लिया जिसका पलनीटकर परिवार की आगे की पांच पीढ़ियों ने वर्ष 2005 तक निर्वहन किया ।

पलनीटकर परिवार द्वारा एक सौ दस वर्षों तक इस ऐतिहासिक महोत्सव के आयोजन का दायित्व संभालने के बाद वर्ष 2005 में अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा इस आयोजन का जिम्मा लिया गया और तब से यह आयोजन अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा ही आयोजित किया जाता है लेकिन सुखद बात यह है कि पलनीटकर परिवार की छठी पीढ़ी इस आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाह करती है।

गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव की इस 131 वर्ष की अनवरत यात्रा में 110 वर्षों तक एक ही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी आयोजन की यह जिम्मेदारी संगीत प्रेम और अपने पूर्वजों की प्रति अटूट आस्थी का विरल उदाहरण है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में इतनी लंबी अवधि तक किसी ग्रामीण परिवार द्वारा किसी शास्त्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन का दायित्व निर्वाहन करने का काम अपने आप में असाधारण उदाहरण है।

देश के सबसे प्राचीनम संगीत महोत्सव में दूसरे नंबर पर स्थापित गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव के संबध में यह तथ्य भी चौकाने वाला है कि बकायन गांव की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 1589 थी,जिसमे कुल 381 परिवार थे । पन्द्रह वर्षो के बाद इस गांव की जनसंख्या आज भी दो हजार से अधिक नहीं है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाला गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव के दिन गांव बकायन एक सांस्कृतिक तीर्थ बन जाता है । गांव के लोग बाहर से आने वाले कलाकारों और श्रोताओं के स्वागत में जुट जाते हैं। भोजन, आवास और आतिथ्य की व्यवस्थाएं सामुदायिक सहयोग से होती हैं। संगीत यहां केवल मंच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे गांव के जीवन का हिस्सा बन जाता है

इस महोत्सव की सबसे खास बात यह है कि इस महोत्सव के संस्थापक बलवंत राव द्वारा दीक्षा प्राप्तक शिष्य 40-40 वर्षों तक लगातार महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर प्रस्तुति देते रहे । समय के साथ इस महोत्सव की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। आज इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली तथा देश के अनेक भागों से गायक, वादक और नर्तक भाग लेते हैं। पद्मभूषण बुद्धादित्य मुखर्जी (सितार) कोलकाता, पद्मश्री सुरेश तलवलकर (पखावज) पुणे, पद्मश्री उल्लास कसालकर,जयतीर्थ मेवुंडी, पं.रघुनंदन पलसीकर, गांधार देशपांडे (गायन) मुंबई व पं. विनोद द्विवेदी (ध्रुपद) कानपुर, प्रख्यात गायिका जानकीबाई और उनकी मां मानकी बाई, तबला वादक आमिर खान, सारंगी वादक दिलदार खान, कथक नृत्यांगना वीणा ठाकुर, हारमोनियम वादक राम प्रसाद पंडा सहित ऐसे तमाम नाम हैं, जो इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद दिलदार खां 35 साल तो मऊरानीपुर रियासत के तबला नवाज़ उस्ताद अमीर खां लगातार 45 साल अपनी इस महोत्सव में आते रहे। जयपुर दूरदर्शन केन्द्र के विख्यात तबला वादक निसार हुसैन खां व उनके पिता उस्ताद काले खां चारों पुत्रों के साथ शामिल होते रहे हैं। इस समारोह के प्रति कलाकारों की यह निष्ठो ही कही जायेंगी कि डबरा के उस्ताद बशीर खां तेज बुखार की स्थिति में भी प्रस्तुति देने आये थे और यहीं दम तोड़ा था।

बकायन गांव में आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सव के ग्रामीण श्रोता भी गजब के हैं। बड़े-बड़े विकट संगीतज्ञों को दो दिन तक सुनने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग अपना सब काम छोड़ दो दिन दिन-रात बकायन में ही जुटे रहते हैं। नृत्य की प्रस्तुतियों में तो महिलाओं का तांता लग जाता है। सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना उमा डोगरा याद करती हैं कि महिलाएं घूंघट की ओट से उनकी प्रस्तुति निहारती थीं तो उन्हें मंच से कहना पड़ता था-जरा घूंघट तो हटा लो।

देशभर में गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व है, लेकिन बकायन गांव के लिए यह दिन संगीत-साधना के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताणद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार से नवाजे गये तबला वादक रामेन्द्रन सिंह सोलंकी बताते हैं कि कलाकार इस महोत्सुव में किसी पारिश्रमिक या व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं।

गुरु पूर्णिमा संगीत महोत्सदव का 132वां आयोजन 29 जौलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरु होकर अपनी परम्मारा का निर्वाहन करते हुए अगले 48 घंटे तक बकायन गांव और आसपास के श्रोताओं को सुरों से आबाद करेगा । बकायन गांव के हनुमान मंदिर परिसर में स्थापित मंच पर दो दिन तक शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां हर बार की तरह इस बार भी आश्वतस्तद करेगी कि बदलते समय में भी सुर समाप्त नहीं होते,वे परंपरा बन जाते हैं।

हिमाचल के चंबा में बाढ़-बारिश से भारी तबाही

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के कई राज्यों में भारी बारिश आफत बन गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद सरोल मोहल्ले समेत कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई।

पानी के साथ आए पत्थरों और मलबे का सैलाब घरों और दुकानों में घुस गया। कई मकानों की पहली मंजिल तक मलबा भर गया। उत्तराखंड में मंगलवार सुबह चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई। रुद्रप्रयाग के कुंड-काकड़ा के बीच केदारनाथ नेशनल हाईवे मलबा

आने से बंद हो गया। सोनप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे भी बंद है, जिसके चलते चारधाम यात्रा दो दिन रोक दी गई है। दिल्ली में मंगलवार सुबह जोरदार बारिश हुई। इससे जगह-जगह सड़कों पर पानी भर गया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार सुबह एमबीए स्कॉलर युवती की करंट लगने से मौत हो गई।

वह गर्ल्स हॉस्टल से अपने विभाग में पढ़ाई के लिए जा रही थी। उधर, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रविवार शाम बिजली गिरने से 11 साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। बारिश बाढ़ से आधे देश के बुरे हाल हैं।

यूपी के 69 हजार शिक्षक भर्ती में जगी न्याय की नई उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट बोला-सभी पक्षों की सहमति बनी तो आर्टिकल-142 से देंगे फैसला

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए एडजस्टमेंट प्लान पर सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति के आधार पर संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत मामले का एकबारगी निस्तारण करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सहमति बनाने और उसे शपथ-पत्र के माध्यम से अदालत को अवगत कराने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है। यदि सभी पक्ष सहमत हो जाते हैं, तो 4 अगस्त 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट आर्टिकल-142 के तहत मामले का निस्तारण कर सकता है। यदि सहमति नहीं बनती, तो कोर्ट लखनऊ डबल बेंच के फैसले के आधार पर आगे की सुनवाई करेगा और सभी पक्षों के 5-5 वकीलों को विस्तार से बहस का मौका देगा। सुनवाई सुबह करीब 11 बजे कोर्ट नंबर 10 में शुरू हुई। कोर्ट ने उन पक्षों को बुधवार (कल) तक का समय दिया, जिन्होंने अभी तक शपथ-पत्र दाखिल नहीं किए हैं।

निशातपुरा स्टेशन से दौड़ी मालवा एक्सप्रेस

सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी भोपाल को मिला चौथा रेलवे स्टेशन

भोपाल (नप्र)। करीब तीन साल से तैयार होकर भी संचालन का इंतजार कर रहे निशातपुरा रेलवे स्टेशन का मंगलवार को औपचारिक शुभारंभ हो गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निशातपुरा स्टेशन से मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यहां उसके नियमित ठहराव की शुरुआत की। साथ ही जबलपुर-वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस के नए स्टॉपेज का भी शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही निशातपुरा भोपाल का चौथा रेलवे स्टेशन बन गया।

कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, विधायक विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से उज्जैन और इंदौर की ओर जाने वाली ट्रेनों को अब इंजन या ट्रैक बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे रेल संचालन और अधिक सुगम बनेगा।

उन्होंने कहा कि मालवा एक्सप्रेस का वैष्णो देवी और सोमनाथ एक्सप्रेस का सोमनाथ धाम से सीधा जुड़ाव होने के कारण निशातपुरा स्टेशन का महत्व और बढ़ गया है। सिंहस्थ सहित भविष्य में बढ़ने वाले यात्री दबाव को देखते हुए यह स्टेशन मुख्य भोपाल रेलवे स्टेशन का भार कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से विकसित निशातपुरा स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास का नया केंद्र बनेगा। इससे आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार, रोजगार व स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।रेलवे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद मध्यप्रदेश में करीब 2,800 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है और प्रदेश का पूरा रेल नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है।

कश्मीर में 50-फीट गहरी खाई में गिरी मंदसौर की बस

● एमपी-राजस्थान के 40 श्रद्धालु सवार थे, अमरनाथ दर्शन के बाद वैष्णो देवी के लिए निकले थे

मंदसौर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के बालटाल से श्रीनगर जा रही मंदसौर की बस मंगलवार को 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे, जो अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे। इनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्री शामिल हैं। हादसे में सभी यात्री घायल हुए हैं। दो को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा सुबह करीब 7 बजे गांदरबल जिले के रंगा मोड़ के पास हुआ। स्थानीय लोगों और राहत-बचाव दल ने सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। घायलों को पहले उप जिला अस्पताल कंगन ले जाया गया। प्राथमिक

उपचार के बाद सभी को सौरा, श्रीनगर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक, ज्यादातर यात्रियों को मल्टीपल इंजरी और हेड ट्रॉमा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने स्थानीय अधिकारियों से घायलों की हालत पर चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी हादसे की जानकारी दी है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल में जुटी है।

मंदसौर की कंपनी ने किराए पर ली थी बस

दुर्घटनाग्रस्त बस अजमेर की है। इसे मंदसौर जिले की मां भगवती यात्रा कंपनी के एजेंट ने अमरनाथ यात्रा के लिए हायर किया था। कंपनी की कुल चार बसें यात्रा पर गई थीं, जिनमें से मंदसौर से गई एक बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार बस में मंदसौर, मल्हारगढ़, नीमच जिले के सुवाखेड़ा और बड़नगर क्षेत्र के भी श्रद्धालु थे। सभी घायलों को श्रीनगर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन घायलों की पहचान और उनकी हालत की जानकारी जुटा रहा है। फिलहाल, यात्रियों के इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस जांच कर रही है। उपराज्यपाल ने घायलों का हाल चाल जाना है।

जापान के कुमामोटो में 6.8 तीव्रता का भूकंप

कुमामोटो (एजेंसी)। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू के कुमामोटो में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई गई थी। जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र कुमामोटो के तटीय शहर उटो के पास 10 किमी की गहराई में था। शुरुआती झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक, भूकंप के झटकों में अब तक 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। साथ ही, 48,300 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली कंपनी क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर ने बताया कि बिजली बहाल करने का काम जारी है। भूकंप के कारण कई इलाकों में सड़कों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं।

छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों, गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं

● पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बहस, गौरव गोगोई ने सरकार को घेरा

कहा- सभी बड़े पदों पर संघ के लोग, एनटीए चीफ पर कार्रवाई क्यों नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले विधेयक पर चर्चा का आगाज हो गया है। पब्लिक एग्जामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में भी पेपर लीक होते थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। वहीं पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान गौरव गोगोई ने केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि सभी बड़े पदों पर संघ के लोग, एनटीए चीफ पर कार्रवाई क्यों नहीं की। गौरव गोगोई ने केंद्र पर अटैक करते हुए कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। उन पर बल प्रयोग हुआ। लड़कियों को थप्पड़ मारे गए। छात्रों पर हमले का आदेश किसने दिया, हम गृह मंत्री से इस बात का जवाब चाहते हैं। किसके आदेश पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई छात्रों ने पेपर लीक चलते जान

दी। **जितेंद्र सिंह ने शुरू की बिल पर चर्चा-** केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक बिल पर चर्चा में कहा कि कल इस विधेयक को पेश किया गया था। असल में पहले के बिल - पब्लिक एग्जामिनेशन्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 - में एक संशोधन है, जिसे भी इसी सरकार ने पेश किया था।

● जितेंद्र सिंह ने गिनाया कब-कब हुआ पेपर लीक- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीए के समय हुए पेपर लीक की लिस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- 2009- रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। 2011- ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 2012-नई दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक। 2013- महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर मैं इनकी लिस्ट बनाता रहा, तो बिल पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा... 2010-एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उत्तर प्रदेश; 2012- तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन।

सभी प्रदर्शनकारियों की एफआईआर वापस होंगी

● सीजेपी ने रात 1 बजे वीडियो जारी कर दी जानकारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि सभी प्रदर्शनकारियों की एफआईआर वापस होंगी। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और रत्ना ने सोमवार रात एक बजे वीडियो जारी कर यह जानकारी दी। सौरव ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि (दिल्ली पुलिस के अफसर) मिलने आए थे। हमने उन्हें बताया कि आशंका है कि सरकार ने जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं होंगे। उन्होंने बिहार सरकार के गृह विभाग की प्रेस रिलीज दिखाई। इसमें लिखा है कि सभी प्रोटेस्टर्स की एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी कोई ऐक्शन नहीं लिया जाएगा। हमारी आशंका थी कि प्रदर्शनकारियों को किसी राज्य में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सरकार ने हमें गारंटी दी है कि ऐसा न हो।

बैरिकेडिंग तोड़ भोपाल में घुसे 2 हजार किसान

सीएम निवास घेरने आगे बढ़े, 7 दिन का राशन साथ लाए, बोले- मांगें पूरी होने पर लौटेंगे

भोपाल (नप्र)। 19 किसान संगठनों के करीब 2000 से ज्यादा किसान सीएम आवास घेरने के लिए भोपाल आ रहे हैं। वे अपने साथ 7 दिन का राशन-पानी भी ला रहे हैं।

मध्यप्रदेश में मूंग की 100 प्रतिशत सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की किसान क्रांति पैदल यात्रा मंगलवार को भोपाल पहुंच गई। मंडीदीप स्थित भोपाल सीमा पर कलियासोत नदी के ब्रिज के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर किसान राजधानी में दाखिल हो गए।

करीब 2 हजार किसान पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े, जबकि उनके पीछे ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों का काफिला भी चलता रहा। किसानों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मांगें पूरी होने तक वापस नहीं लौटेंगे।

भोपाल सीमा पर बैरिकेडिंग तोड़कर किया प्रवेश- मंडीदीप स्थित भोपाल सीमा पर कलियासोत नदी के ब्रिज के पास पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भोपाल सीमा में प्रवेश कर गए। बड़ी संख्या में किसान पैदल आगे बढ़े, जबकि उनके पीछे ट्रैक्टर और अन्य वाहन भी चलते रहे।

जय जवान-जय किसान के नारों के साथ बढ़े किसान- भोपाल में प्रवेश के बाद किसान हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान वे लगातार जय जवान-जय किसान के नारे लगा रहे हैं। किसानों का पैदल मार्च जारी है, जबकि उनके पीछे ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों का काफिला भी आगे बढ़ रहा है।

7 दिन का राशन-पानी साथ लाए किसान- भोपाल कूच में शामिल किसान लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ आए हैं। वे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सात दिन का राशन और पानी लेकर पहुंचे हैं। कई किसान पहले से दाल-बाटी बनाकर भी साथ लाए हैं। उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और वे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं।

19 किसान संगठन आंदोलन में शामिल- संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के 19 किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं। सुबह किसानों को औबेदुल्लागंज टोल प्लाजा के पास कुछ देर रोका गया था। प्रशासन ने किसान नेताओं से बातचीत कर उन्हें इंतजार करने का आग्रह किया, लेकिन बाद में किसान पैदल मार्च पर निकल पड़े। अब आंदोलनकारी भोपाल में प्रवेश कर चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे हैं।

नेताओं का आरोप- गांवों में ही रोक रहे- किसान संगठनों के पदाधिकारियों का आरोप है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए उनके कई साथियों को गांवों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। उनका कहना है कि विदिशा, रायसेन, हरदा, नर्मदापुरम और बुधनी के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। किसान नेताओं का आरोप है कि जगह-जगह पुलिस बल तैनात है और किसानों को भोपाल आने से रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग वाले स्थानों पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही किसान नेताओं की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

पुलिस की नरमी, बैरिकेड पार कर भोपाल में दाखिल होते रहे किसान- पुलिस जगह-जगह बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सख्त कार्रवाई से बचती नजर आ रही है। हल्की रोक-टोक के बाद किसान आसानी से बैरिकेड पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में किसान अब भोपाल सीमा के भीतर प्रवेश कर चुके हैं और उनका मार्च लगातार जारी है।

हाथों में तिरंगा, जय जवान-जय किसान के नारों के साथ बढ़े किसान- भोपाल में प्रवेश के बाद किसान हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान वे लगातार जय जवान-जय किसान के नारे लगा रहे हैं। किसानों का पैदल मार्च जारी है, जबकि उनके पीछे ट्रैक्टर और अन्य वाहनों का काफिला भी आगे बढ़ रहा है।

किसान को पुलिस रोक नहीं सकी

मंडीदीप स्थित भोपाल सीमा पर कलियासोत नदी के ब्रिज के पास की गई पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर किसान भोपाल में प्रवेश कर चुके हैं। बड़ी संख्या में किसान पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े, जबकि उनके पीछे ट्रैक्टर और अन्य वाहन भी चलते रहे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन किसान बैरिकेडिंग पार कर भोपाल सीमा में दाखिल हो गए।

980 रुपए का साइबर फ्रॉड फ्रीज कर दिए 2.51 करोड़

- हाईकोर्ट बोला- पूरी नहीं, सिर्फ विवादित राशि पर रोक लगाएं, पूरे प्रदेश के लिए गाइडलाइन जारी की

जबलपुर (नप्र)। भोपाल की रहने वाली महिला कारोबारी अर्चना शिवहरे के बैंक खाते में मौजूद 2.51 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को महज 980 रुपए के संदिग्ध साइबर ट्रांजेक्शन के आधार पर फ्रीज किए जाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। साइबर पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेशभर के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां पूरे बैंक खाते को फ्रीज करने के बजाय, जहां तक संभव हो, केवल विवादित राशि पर ही लियन या डेबिट फ्रीज लगाएं। पूरे खाते को फ्रीज करना अंतिम और असाधारण परिस्थिति में ही अपनाया जाने वाला कदम होना चाहिए। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि संदिग्ध लेन-देन की राशि सीमित है, तो पूरे खाते पर रोक लगाना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों को कथित अपराध से जुड़ी राशि और खाते में मौजूद वैध धनराशि के बीच अंतर करना चाहिए तथा केवल उतनी ही रकम पर रोक लगानी चाहिए, जितनी जांच के लिए आवश्यक हो। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें 980 रुपए के संदिग्ध साइबर ट्रांजेक्शन के आधार पर 2,51,72,192.57 रुपए वाले पूरे चालू खाते को फ्रीज कर दिया गया था।

ट्विशा केस-

दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ी

बचाव पक्ष ने वॉइस सैंपल को लेकर उठाई आपत्ति, सीबीआई बोली- जांच जारी है

भोपाल (नप्र)। ट्विशा केस में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल रिमांड) 11 अगस्त तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान ट्विशा के पिता और भाई भी अदालत में मौजूद रहे और पूरी कार्यवाही देखी। शुभांग दीक्षित के अनुसार, पेशी के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि सीबीआई का यह दावा सही नहीं है कि उन्होंने वॉइस सैंपल देने में सहयोग नहीं किया। बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी कहा कि वॉइस सैंपल लेने के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों का व्यवहार उचित नहीं था और इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

कोर्ट ने कहा- यह मुद्दा जमानत सुनवाई में उठ चुका है- अधिवक्ता दीक्षित ने बताया कि इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वॉइस सैंपल और उससे जुड़े तर्क पहले जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान भी उठाए जा चुके हैं। चूंकि जमानत आवेदन पर फैसला हो चुका है, इसलिए वर्तमान रिमांड की सुनवाई में इस मुद्दे का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि इस संबंध में अदालत ने अपने लिखित आदेश में कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की।

अशोकनगर में स्टूडेंटों ने तीन किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई

- पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया

अशोकनगर (नप्र)। अशोकनगर में पुलिस द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के तहत मंगलवार को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत शहर में स्कूली विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता से विशाल मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। शहर के सेन तिराहे से त्रिदेव मंदिर तक करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम का निरीक्षण किया और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

जिलेभर में चले जागरूकता कार्यक्रम- अभियान केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुंगावली में भी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया तथा नशामुक्त समाज बनाने का संदेश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि नशे के खिलाफ माइक्रोबीट स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंच सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अभियान के तहत स्कूली विद्यार्थियों की पेंटिंग प्रतियोगिता सहित कई रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

वेटलैंड पर 'मड रैली'-स्टंटबाजों पर एफआईआर

10 कारें जब्त, कलियासोत डैम किनारे हुई थी रैली; कार नंबरों से मालिकों की पहचान

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कलियासोत डैम के वेटलैंड एरिया में खतरनाक 'मड रैली' और हुड़दंग पर विवाद के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टंटबाजों पर एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 10 कारें जब्त की है। नंबरों के जरिए मालिकों की तलाश की जा रही है। दोपहर बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी।

रातीबड़ पुलिस ने स्टंटबाजी में उपयोग की गई जिप्सी, थार जैसी गाड़ियां जब्त की है। वहीं स्टंटबाजों को दबोचा। इनके विरुद्ध खतरनाक ढंक से वाहन चलाने, उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने, मानव जीवन पर संकट उत्पन्न करने, प्राकृतिक जलाशयों को प्रदूषित करने, संक्रमण फैलाने पर धारा 281, 170, 271, 279 बीएनसी एवं 184 एमवी एक्ट जैसी धाराओं पर केस दर्ज किया गया।

यह मड रैली रविवार 28 जुलाई को निकाली गई थी। इस पर पर्यावरणविदों ने आपत्ति जताते हुए इसे जलीय जीव-जंतु के लिए बड़ा खतरा बताया था। साथ ही मड रैली के आयोजकों पर एफआईआर की मांग भी की थी। नेशनल ग्रीन ट्रब्नल (एनजीटी) में भी याचिका दाखिल की जा रही है।

ज्योतिषाचार्य ने जताए युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत

31 जुलाई से बनेगा 'बंधक योग', 15 अगस्त तक सभी ग्रह राहु-केतु के बीच रहेंगे

भोपाल (नप्र)। ज्योतिष मठ संस्थान के अनुसार सोमवार रात 8.42 बजे से शनि वक्री हो गए हैं। संस्थान का कहना है कि गुरु पहले से ही अतिचारी (शीघ्रगामी) हैं और इन दोनों ग्रहों की यह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ मानी जाती है। संस्थान ने दावा किया है कि इस ग्रह स्थिति के कारण दुनिया में युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका है।

ज्योतिषाचार्य एवं भविष्यवक्ता पंडित विनोद गौतम ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु के अतिचारी और शनि के वक्री होने का विशेष महत्व बताया गया है। उन्होंने शास्त्रीय संदर्भ देते हुए कहा कि ऐसी ग्रह स्थिति को देश-दुनिया के लिए संकटकाल का संकेत माना जाता है। उनके अनुसार आधुनिक हथियारों से युद्ध, समुद्री क्षेत्रों में तनाव और भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं की आशंका भी इस दौरान बढ़ सकती है।

पंडित गौतम ने बताया कि 31 जुलाई की सुबह 6.20 बजे चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाएंगे। इसे ज्योतिष में 'बंधक योग' कहा जाता है। उनका दावा है कि यह योग 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में जन्म लेने वाले नवजातों की कुंडली में कालसर्प दोष बनने की संभावना रहेगी।

उन्होंने कहा कि बंधक योग के प्रभाव से कई देशों की संप्रभुता, समुद्री गतिविधियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वहीं भारत की प्रभाव राशि कुंभ और मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि मकर होने के कारण शनि की वक्री चाल का असर देश और प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और मध्य प्रदेश में राजनीतिक फेरबदल की संभावना से भी इनकार नहीं किया।

वायरल गर्ल को केरल हाईकोर्ट ने दी सुरक्षा

भोपाल। इंटरफेथ मैरिज से जुड़े चर्चित वायरल गर्ल मामले में केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि युवती को अदालत की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति के हवाले नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा- न ही लड़की की इच्छा के विरुद्ध अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाया जाएगा। युवती को पहले से मिली पुलिस सुरक्षा फिलहाल जारी रहेगी।

एससीएसटी के आदेश पर कोर्ट ने जताई हैरानी- सुनवाई के दौरान अदालत ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया था कि युवती को विधि अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा जाए और उसकी संशोधित जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज हाईकोर्ट के सामने पेश किए जाएं।

बर्थडे पर 12वीं की छात्रा ने लगाई फांसी

फ्रेंड्स केक लेकर पहुंचीं तो फंदे पर लटकी मिली गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कर रही थी पढ़ाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित आदिवासी कन्या छात्रावास में रहकर 12वीं की पढ़ाई और जेईई की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा ने रविवार शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को उसका 17वां जन्मदिन था। सहेलियां केक लेकर बर्थडे मनाने पहुंचीं तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। सेंट्रल लॉक खुलने पर छात्रा कमरे में फंदे पर लटकी मिली। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार बताते हुए माता-पिता से माफी मांगी है। मृतका की पहचान अलीराजपुर निवासी दर्शन मिनामा पिता रमेश मिनामा के रूप में हुई है। वह अनंत हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा थी और एसेंट करियर प्वाइंट से जेईई की तैयारी कर रही थी।

रूम मेट 20 दिन से गई हुई थी गांव

पुलिस के अनुसार, दर्शन सितंबर 2025 से छात्रावास में रह रही थी। रविवार शाम करीब 5:30 बजे वह कोचिंग से लौटकर अपने कमरे में गई थी। उसकी रूममेट मनीषा नरगावा पिछले 20 दिनों से अपने गांव छुट्टी पर गई थी, जिसके कारण वह कमरे में अकेली थी। शाम करीब 6 बजे छात्रावास की अन्य छात्राएं उसका जन्मदिन मनाने के लिए कमरे पर पहुंचीं, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। लगातार चार-पांच मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद सेंट्रल लॉक खुल गया। अंदर जाकर देखा तो छात्रा रस्सी के फंदे से लटकी हुई थी। छात्रावास की वार्डन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

कमरे से मिला सुसाइड नोट- घटना की सूचना पर पुलिस, एफएसएल टीम और फोटोग्राफर मौके पर पहुंचे। कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। सुसाइड नोट में छात्रा ने आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है तथा माता-पिता से माफी मांगी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने छात्रा के डिप्रेशन में होने की बात कही है, हालांकि आत्महत्या के कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। परिजनों की मौजूदगी में मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां की सोने के हत्थे वाली तलवार मिली

शिवपुरी के सर्वे में हाथ लगे 50 ऐतिहासिक फरमान

शिवपुरी (नप्र)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से इतिहास के पन्नों से जुड़ी एक बेहद रोमांचक और बड़ी खबर सामने आई है। जिले के करैरा इलाके में 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों का सर्वे चल रहा था। इसी दौरान सर्वे टीम के हाथ एक ऐसा खजाना लगा, जिसने इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया। टीम को मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर की एक सोने के हत्थे वाली दुर्लभ तलवार मिली है, जिस पर फारसी भाषा में खास उकेर दर्ज है।

यह अनमोल तलवार करैरा किले के कमांडेंट रहे सैयद सालार के नौवीं पीढ़ी के वंशज और वकील इत्रत जैदी के पास संरक्षित परिवार के संग्रह से मिली है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह बची हुई बेहद दुर्लभ मुगलकालीन हथियारों की सूची में शुमार होगी।

फारसी में लिखी गई है गवाही और इतिहास- सर्वे टीम का नेतृत्व करने वाले वसीम खान के मुताबिक, इस तलवार की सबसे बड़ी खासियत इस पर उकेरी गई फारसी इबारत है। सोने

से की गई इस लिखावट में दर्ज है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे करैरा किले के कमांडर सैयद सालार को शाही इनाम के तौर पर भेंट किया था।

इतिहासकारों के अनुसार, इस हथियार की बनावट साल 2007 में सोथबी की नीलामी में बिके शाहजहां के निजी तलवार से काफी मेल खाती है, जिसे तब भारी कीमत पर कतर के दोहा स्थित म्यूज़ियम ऑफ़ इस्लामिक आर्ट के लिए खरीदा गया था। इस नई खोज पर मिले शिलालेख से यह साबित होता है कि यह मुगल काल का एक प्रामाणिक और शाही तोहफा है।

50 मुगलकालीन फरमान और हाथ से लिखी कुरान भी मिली- तलवार के अलावा इस सर्वे में मुगल काल के लगभग 50 राजसी फरमान भी मिले हैं, जिनमें शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब के शासनकाल के मूल शाही आदेश शामिल हैं। इसके साथ ही कुरान शरीफ की एक हस्तलिखित प्रति भी मिली है। जानकारों का कहना है कि ये दस्तावेज इस बात की सटीक गवाही देते हैं कि कैसे मुगल दरबार से प्रांतीय ठिकानों तक शाही हुकूमत और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता था।

परिवार का कहना है कि कई बड़े खरीदारों ने इसे खरीदने के लालच दिए, लेकिन उनके बुजुर्गों ने कभी इसे नहीं बेचा। अब इन सभी ऐतिहासिक धरोहरों का ज्ञान भारतम मिशन के तहत संरक्षण, डिजिटलाइजेशन और विस्तृत एपिग्राफिक अध्ययन किया जाएगा।

संपादकीय

नीयत सुधरना भी जरूरी

मोदी सरकार विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले रोकने के लिए जो सख्त कानून लाई है, वह स्वागत योग्य है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इससे परीक्षा तंत्र में सच में अमूल सुधार होगा अथवा लोग इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। क्योंकि कोई भी सुधार नैतिक प्रतिबद्धता चाहिए। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया। सरकार का दावा है कि इससे पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसमें 10 साल की सजा, भारी जुर्माना, विशेष अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय का प्रावधान किया गया है। इसके पहले देश में लागू लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 लागू था। जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित धोखाधड़ी को रोकना था। उस कानून में अधिकांश गंभीर अपराधों के लिए 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम रू. 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान था। जबकि नए संशोधन विधेयक में संगठित अपराधों के लिए दंड और अधिक कड़ा किया जा रहा है। नए कानून में प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी लीक कराने, परीक्षा प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने या अपराध में मिलीभगत करने वालों को अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। कई मामलों में सेवा प्रदाता कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारियों पर 10 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्तावहै, जहां अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी। साथ ही चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने की बात है। पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में 15 प्रकार की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इनमें प्रश्नपत्र लीक करना, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना और परीक्षा प्रक्रिया में अन्य प्रकार की धोखाधड़ी शामिल हैं। विधेयक में परीक्षाओं के लिए नए गाइडलाइंस तय करने का भी प्रस्ताव है। इसमें परीक्षा केंद्रों का प्री-ऑडिट, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक जांच, सुरक्षा व्यवस्था, सीट आवंटन, प्रश्नपत्र तैयार करने और अपलोड करने की प्रक्रिया, परीक्षा में निगरानी, परीक्षा के बाद की गतिविधियां और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि सरकार पेपर लीक मामले में एनटीए के 47 संविदाकर्मी अधिकारियों को बर्खास्त कर चुकी है। इसके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के दो सचिवों को बदला था। इस एक्शन के साथ ही अब एटीए के आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव और तकनीकी सुधार लागू किए जाने की तैयारी है, जिससे परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। इधर दिल्ली पुलिस ने देश की सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के लिए एसटीएफ का गठन किया है। इसके दायरे में यूपीएससी से एनटीए तक सभी प्रमुख परीक्षाएं होंगी। पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। बेशक पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जबर्दस्त छात्र आंदोलन के बाद सरकार जागी है। छात्रों के रोष के आगे बेबस दिखी सरकार ने अपने शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा ले लिया। लेकिन अभी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये है शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की। उस दिशा में कोई ठोस कदम उठता अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जहां कठोर दंड की बात है तो हत्या के लिए सबसे बड़ा दंड मृत्युदंड है, फिर भी हत्याएं कहां रूक रही हैं?

नजरिया

राजेंद्र रवि

लेखक शहरी योजनाकार हैं तथा इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी (आईडीएस) दिल्ली के निदेशक हैं।

मानसून नहीं, शहरों की व्यवस्था समस्या

हर मानसून में भारत के शहर एक जैसी कहानी दोहराते हैं। तेज़ बारिश की पहली बौछार पड़ते ही सड़कें पानी में डूब जाती हैं, लोग घंटों जाम में फँसे रहते हैं, वाहन खराब हो जाते हैं और सोशल मीडिया जलमग्न सड़कों, उफनती नालियों तथा धँसती सड़कों की तस्वीरों से भर जाता है। पानी उतरने के बाद सरकारें जाँच के आदेश देती हैं, संबंधित एजेंसियाँ सुधार के वादे करती हैं और अस्थायी मरम्मत शुरू हो जाती है, लेकिन अगले मानसून तक वही स्थिति फिर सामने आ जाती है।

हाल ही में दिल्ली-एनसीआर (नेशनल केपिटल रीजन) में हुई भारी वर्षा ने एक बार फिर भारत के शहरी बुनियादी ढाँचे की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। दिल्ली में प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ और अनेक रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। गुरुग्राम - जो वर्षों से मानसून के दौरान जलभराव के लिए कुख्यात रहा है - में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, हीरो होंडा चौक और सोहना रोड जैसे प्रमुख मार्ग पानी में डूब गए, जिससे देश के प्रमुख कॉर्पोरेट केंद्रों में से एक लगभग ठहर गया।

नोएडा में अंडरपास जलमग्न हो गए, नालियाँ उफनने लगीं और भीषण जाम लग गया। वहीं गाज़ियाबाद और फरीदाबाद में कई कॉलोनियाँ पानी में डूब गईं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और लोगों की आवाजाही बुरी तरह बाधित हुई। एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश के बाद सड़कें धँस गईं, जिसने केवल निर्माण की खामियों को ही नहीं, बल्कि शहरी नियोजन, इंजीनियरिंग और रखरखाव की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को भी उजागर कर दिया।

ये बार-बार होने वाली विफलताएँ केवल असामान्य रूप से अधिक वर्षा का परिणाम नहीं हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि भारतीय शहरों की योजना, शासन व्यवस्था, वित्तपोषण और रखरखाव की पूरी प्रणाली में गंभीर संरचनात्मक कमियाँ मौजूद हैं। अब बहस इस बात पर नहीं रह गई है कि जलवायु परिवर्तन अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा रहा है या नहीं - यह निर्विवाद सत्य है। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हमारे शहर इस नई जलवायु वास्तविकता के अनुरूप स्वयं को पर्याप्त गति से ढाल पा रहे हैं? उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है।

भारत के अधिकांश शहरी बुनियादी ढाँचे का निर्माण उन ऐतिहासिक वर्षा पैटर्न के आधार पर किया गया था, जो आज की जलवायु परिस्थितियों से मेल नहीं खाते। दूसरी ओर, तीव्र शहरीकरण ने मिट्टी और हरित क्षेत्रों की जगह कंक्रीट बिछा दिया है, जिससे भूजल का पुनर्भरण कम हुआ है और वर्षा जल का बहाव कई गुना बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में झीलें, आर्द्रभूमियाँ, गाँवों के तालाब और प्राकृतिक जल-निकासी मार्ग या तो अंधाधुंध शहरी विस्तार की भेंट चढ़ गए हैं या फिर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि वे अपना प्राकृतिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जो पानी पहले प्राकृतिक रूप से बाढ़ क्षेत्रों में फैल जाता था, वह अब घनी आबादी वाले कंक्रीट के जंगलों में फँस जाता है। नतीजा स्पष्ट है - जब भारी बारिश होती है तो पानी के निकलने के लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर भी केवल जलवायु परिवर्तन यह नहीं समझा सकता कि हर वर्ष वही दृश्य क्यों दोहराए जाते हैं। इसके लिए शासन व्यवस्था की विफलताएँ भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

एनसीआर संस्थागत विखंडन का एक स्पष्ट उदाहरण है। केवल दिल्ली में ही नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली जल बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा कई अन्य एजेंसियाँ शहरी बुनियादी ढाँचे के अलग-अलग हिस्सों की जिम्मेदारी संभालती हैं। दिल्ली के बाहर गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद अलग-अलग नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन वर्षा का पानी प्रशासनिक सीमाओं को नहीं पहचानता।

इसके परिणाम हर जगह दिखाई देते हैं। सड़कों का पुनर्निर्माण भूमिगत उपयोगिताओं के साथ समन्वय किए बिना कर दिया जाता है। नालियाँ आगे के बड़े जल निकासी नेटवर्क से जुड़े बिना ही समाप्त हो जाती हैं। बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएँ व्यापक जल-विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) अध्ययन के बिना शुरू कर दी जाती हैं। रखरखाव की जिम्मेदारियाँ कई एजेंसियों में बँटी होने के कारण बाढ़ आने पर जवाबदेही भी बिखर जाती है।

भारत के शहरी बुनियादी ढाँचे की सबसे कमजोर कड़ी उसका रखरखाव है। राजनीतिक प्राथमिकताएँ स्वाभाविक रूप से एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, मेट्रो विस्तार और स्मार्ट सिटी जैसी दिखाई देने वाली परियोजनाओं पर केंद्रित रहती हैं। इसके विपरीत मानसून से पहले नालों की सफाई, रिटेनिंग वॉल की जाँच, पुलियों की मरम्मत, भूमिगत उपयोगिताओं का मानचित्रण और पुराने हो चुके बुनियादी ढाँचे की नियमित निगरानी जैसे कम आकर्षक लेकिन अत्यंत आवश्यक कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता।

दिल्ली-एनसीआर में हाल ही में हुई सड़क धँसने की घटनाएँ इसी उपेक्षा का परिणाम हैं। सड़कें किसी एक बारिश से नहीं धँसतीं। ऐसी घटनाएँ आमतौर पर वर्षों से पाइपलाइन रिसाव, ठीक से न दबाई गई मिट्टी, पुराने उपयोगिता नेटवर्क, अपर्याप्त जल निकासी या बार-बार खुदाई के बाद उचित पुर्नस्थापन न होने के कारण सतह के नीचे जमा होती कमजोरियों का परिणाम होती हैं। भारी बारिश केवल उन कमजोरियों को उजागर कर देती है जो लंबे समय से विकसित होती रही हैं। इसलिए 'जलवायु अनुकूलता' (क्लाइमेट रेज़िलिएंस) को केवल पर्यावरणीय चिंता के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसे शहरी बुनियादी ढाँचे की योजना का केंद्रीय सिद्धांत बनाना होगा।

इस परिवर्तन में प्रकृति-आधारित समाधानों को कहीं अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। पुनर्जीवित आर्द्रभूमियाँ, शहरी वन, पानी सोखने वाले फुटपाथ, बायोस्वेल, वर्षा उद्यान, विकेंद्रीकृत वर्षा-जल संचयन प्रणाली और संरक्षित शहरी झीलें वर्षा-जल के बहाव को काफी हद तक कम कर सकती हैं तथा भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दे सकती हैं। गुरुग्राम के लुप्त होते प्राकृतिक नाले और दिल्ली की सिकुड़ती आर्द्रभूमियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि पारिस्थितिक बुनियादी ढाँचे की उपेक्षा अंततः इंजीनियरिंग आधारित ढाँचे को भी कमजोर कर देती है।

नागरिकों को यह प्रश्न पूछने का भी अधिकार है कि सार्वजनिक निवेश वास्तव में कितनी स्थायी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एनसीआर में हर वर्ष करदाताओं के करोड़ों रुपये सुरंगों, अंडरपासों और प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा होते ही इनमें से अनेक संरचनाएँ जलमग्न हो जाती हैं—चाहे वह प्रगति मैदान सुरंग हो या क्षेत्र के अनेक अंडरपास। इससे एक बड़ा सवाल उठता है—क्या हमारी सड़कें केवल वाहनों की आवाजाही के लिए बनाई जा रही हैं, या उन्हें उन जलवायु परिस्थितियों में भी सुचारु रूप से कार्य करने योग्य बनाया जा रहा है जिनका उन्हें सामना करना है?

जैसे-जैसे जलवायु की चरम स्थितियाँ सामान्य होती जा रही हैं, भारत के शहरों के सामने एक निर्णायक विकल्प है। वे हर मानसून को एक अप्रत्याशित आपदा मानते हुए उसी पुराने ढर्रे पर चलते रह सकते हैं, या फिर इसे शहरी शासन और बुनियादी ढाँचे की वार्षिक परीक्षा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। दिल्ली-एनसीआर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वास्तविक लचीलापन केवल चौड़ी सड़कें या बड़े नाले बनाने से नहीं आता। इसके लिए ऐसे शहरों का निर्माण करना होगा जिनकी योजना दूरदर्शी हो, शासन प्रभावी हो, रखरखाव नियमित और जिम्मेदार हो तथा जो बदलती जलवायु की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। (सप्रेस)

अंतर्राष्ट्रीय बाघ

डॉ. रमेश ठाकुर

लेखक समाजसेवी हैं।

बाघों की घटती आबादी को रोकना अब भी चुनौती

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान भारत सरकार 'अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस' को मनाने का मुख्य मकसद विश्व भर में तेजी से घटती बाघों की आबादी को रोकने एवं उनके संरक्षण के प्रति समूची दुनिया को जागरूक करना होता है। आज का दिन जंगल की शान कहे जाने वाले बाघों के लिए समर्पित है। सालाना ये दिन 29 जुलाई को पूरे संसार में मनाया जाता है। शुरुआत रूस स्थित 'पीटरर्सबर्ग टाइगर संरक्षण शिखर सम्मेलन' के दौरान वर्ष-2010 में की गई थी। विश्व में बाघों की संख्या करीब 78 फीसदी तक घट चुकी है। गनीमत है कि भारत बाघों के मामले में अभी भी टॉप पर है। वैश्विक स्तर के आंकड़ों पर गौर करें, तो अनुमानित, बाघों की संख्या पूरे विश्व में लगभग 5,500 के बीच है। इनमें से 72 प्रतिशत आबादी अकेले हिंदुस्तान में ही है। 2022 बाघ जनगणना में भारतीय जंगलों और टाइगर रिजर्व में 3,682 जंगली बाघ थे, इनमें पिछले दो वर्षों में इजाफा ठीक ठाक हुआ। 'ग्लोबल टागईर दिवस-2025' की थीम थी, 'हमारे हाथों में हैं बाघों का संरक्षण'।

बाघ आबादी में भारत के अलावा दूसरे पायदान पर रूस है। अखिल भारतीय बाघ जनगणना-2022 में बाघों की जितनी संख्या बताई गई थी, उनमें अब 12 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि, संपूर्ण संख्या अगली गणना में ही सामने आएगी। बाघ संरक्षण की दिशा में बीते कुछ वर्षों से सराहनीय प्रयास हुए हैं। बाघों का सर्वेक्षण आधुनिक तकनीकों से किया जाने लगा है। प्रत्येक टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में कैमरे लगवाए गए हैं, ताकि उनकी मुकम्मल आबादी का पता चल सके और उनकी चहलकदमी पर नजर रखी जा सके। पिछली बाघ जनगणना के दौरान मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एकाध बाघ दिखे, तो केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को उस जगह को 58 वां टाइगर रिजर्व स्थापित कर दिया जिसका नाम 'माधव राष्ट्रीय उधान' रखा गया। यह प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है।

गौरतलब है कि भारत में बाघों की गणना प्रत्येक 5 साल बाद की जाती है पिछली गणना 2022 में हुई थी, अगली गणना मार्च-2027 में करवाने का प्रस्ताव पारित है। बाघों की आबादी जितनी होनी चाहिए, उतनी है नहीं? बाघ संरक्षण पर केंद्र सरकार सालाना करीब 250 से 290 करोड़ रूपए खर्च करती है। वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में रखे गए प्रत्येक बाघ पर साल में 20 लाख से ज्यादा खर्च होता है। आजादी से पूर्व 100 साल पहले यानी 1926 के आसपास में हिंदुस्तान बाघों की आबादी सर्वाधिक एक लाख से भी अधिक हुआ करती थी, जो घटती-घटती आज कुछ हजारों तक ही सिमट गई। उत्तराखंड स्थित सिर्फ जिम कॉर्बेट में ही हजारों बाघ पाए जाते थे। हालांकि, सर्वाधिक संख्या आज भी वहीं है। पिछली गणना में 231 बाघ बताए गए थे। इस समय मध्यप्रदेश में 785, कर्नाटक में 524 बाघ हैं।

बाघों के लुप्त होते कारणों में आवासों की कमी, वन-विखंडन, अवैध शिकार, मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे मुख्य वजहें हैं। अगर ये रूक जाएं, तो बाघों की संख्या एकाएक बढ़ जाएगी। एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां बाघ पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं उनमें, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। कुछ मुल्क विलुप्ति की कगार पर हैं। बाघों का अवैध शिकार समूचे संसार में तेजी से जारी है। होता क्यों है? ये भी जानना जरूरी है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बाघों के अंगों की सदैव से भारी डिमांड रही है जिनमें एशियाई बाघों की सबसे ज्यादा। बाघ संरक्षण क्षेत्रों में और सख्तियां बरतने की जरूरत है। कानूनों को कठोर और जुर्माने का भारी भरकम प्रावधान किए जाने की दरकार है। ताकि, कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले सौ बार सोचे। पिछले एक वर्ष में विभिन्न राज्यों में करीब 75 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, कईयों को जेल भी हुई। नरसिंहपुर, बालाघाट और बांधवगढ़ में बाघों के अवैध शिकार व अंगों की तस्करी मामलों मार्च 2025 में एक साथ दर्जनों शिकारियों की अरेस्टिंग हुई थी। आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के तहत कार्रवाही की जाती है जिसमें 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान है। इसे रिफॉर्म किए जाने की अब जरूरत है।

मालूम हो, कि जंगली बाघ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सामंजस्य को बनाए रखने में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। भारत में टाइगरों के संरक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरों पर विभिन्न अभियान बीते एकाध दशकों से जारी हैं। इन अभियानों के निरंतर चलते रहने से ही भारत में इस समय 58 टाइगर रिजर्व स्थापित हैं। ये बाघ रिजर्व 19 राज्यों में फैले हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं। करीब 30 पहले भारत में बाघों की आबादी अचानक से घटनी शुरू हुई, तो सरकार ने 'टाइगर टास्क फोर्स' का गठन किया। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 जुलाई 1973 को 'प्रोजेक्टर टाइगर' आरंभ करके घटती बाघों की आबादी को किसी तरह रोकना शुरू किया। इस प्रयोग से जबरदस्त फायदा भी हुआ।

बाघ संरक्षण निर्भर प्रजाति है। बाघों के संरक्षण में उनके रहने के निवास यानी अभयारण्यी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पर, इन जगहों पर लगातार बढ़ती शिकारियों की आमदगी ने उनकी शांत जिंदगी में खलल पहुंचा दिया है। शिकारी ज्यादातर बाघ अभयारण्यों के ईद-गिर्द घात लगाए बैठे होते हैं। बाघ को देखते ही उसका शिकार कर देते हैं। कई बार खबरें ऐसी भी आई कि शिकारियों का साथ वन्य कर्मी भी देते है। ऐसे गंभीर आरोप में कर्नाटक के कई वन्य कर्मी पकड़े भी गए। इस सिंडिकेट को किसी भी तरह से रोके जाने की दरकार है। अगर नहीं रोका गया हुआ, तो भारत वैश्विक स्तर पर बाघ आबादी का पहला पायदान खो देगा।

क्या मप्र में बाघों की बहार रहेगी कायम

बाघ गणना

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

वनराज, बाघ, टाइगर, जंगल के राजा, गिर के शेर या सिंह जिस नाम से भी पुकारें अब उनकी मौजूदगी आबादी क्षेत्रों के और भी नजदीक बढ़ती जा रही है। चतुर, चालाक तथा अक्सर कहीं भी घुसपैठ करने वाले तेंदुए भी आवासीय इलाकों में आते - जाते रहते हैं। उधर प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बड़े शोर- शराबे के साथ लाये गये चीते भी अपनी हदों से बाहर निकलकर आसपास के जिलों तो कभी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा तक निकल पड़ते हैं। सो, टाइगर हो, तेंदुए या चीते उनकी हदें उनसे पूछकर तो तय की नहीं गई हैं, तब वे स्वच्छंद विचरण करेंगे ही।

तात्पर्य यह है कि इन खतरनाक, खूंखार जंगली प्राणियों के विचरण की जगह या इलाका किसी सीमा का पाबंद कैसे हो सकता है। इंसानों ने भी कोई कमी तो छोड़ी नहीं है और इनके विचरण इलाकों में इंसानी घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है। तो फिर कैसे माना जाये कि बाघ, तेंदुए और चीते आबादी के निकट और खेतों तक क्यों आ जाते हैं। बीते साल भी ऐसे अनेक उदाहरण सामने आये जहां ये खतरनाक जानवर आबादी इलाकों के नज़दीक आ धमकते हैं।

हरेक चार साल में होने वाली बाघों की गणना (टाइगर सेंसश) इस साल 2026 में भी हुई है जिसके परिणाम आने वाले वक्त या बाघ दिवस पर भी घोषित हो सकते हैं। बाघों की गणना देश के साथ मध्यप्रदेश के भी 9 टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और 26 वन्य जीव अभयारण्य में की गई है। यह गणना बाघों के पग मार्क के साथ कैमरा ट्रेकिंग की आधुनिक पद्धति से की गई है। वन विभाग के अमले ने इस काम को अंजाम दिया है।

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) के सूत्रों के अनुसार इस बार देश भर में बाघों की संख्या बढ़कर 4 हजार या इससे ज्यादा होने की संभावना है जो 2022 की गणना में 3682 थी। इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।

प्रबल संभावना यही है कि देश के साथ खासकर टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश में इनकी संख्या में वृद्धि होगी। पिछली टाइगर सेंसश में 785 बाघों की संख्या के साथ मध्यप्रदेश पुनः सिरमौर बना था। इस बार भी उम्मीद यही की जा सकती है कि यह तमगा मध्यप्रदेश के पास बना रहेगा। अखिल भारतीय गणना 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक 3907 तेंदुए मध्यप्रदेश में पाये जाते हैं। उधर तकरीबन विलुप्त हो चुके चीतों को पुर्नस्थापित करने में मध्यप्रदेश देश का एक मात्र राज्य हैं। चीतों की संख्या भी बढ़कर लगभग 48 हो गई है।

तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि देश भर में बीते साल विभिन्न कारणों से बाघों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की संख्या 161 है, इसमें मध्यप्रदेश में ही 50 से अधिक बाघों की मौत शामिल है। बाघों की ये मौतें कथित तौर पर करंट लगने, रेल्वे ट्रेक, आपसी संघर्ष, बीमारी या स्वाभाविक रूप से होना बताया जाता है। अपवाद स्वरूप शिकार से हुई मौत का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है।

बीते जून माह की 28 तारीख रविवार की रात 8.30 बजे का वक्त रहा होगा। किसी कार्य से लौटते समय मैंने देखा कि भोपाल के साक्षी ढाबे के थोड़ा आगे से लेकर कलियासोत तालाब के किनारे दोनों तरफ दुपहिया वाहन और कारें खड़ी हुई थी। कतिपय लोग, युवक- युवतियों के झुंड पेड़ों के समीप तो कभी झाड़ियों के पास मंडरा रहे थे। स्ट्रीट लाइट नहीं थी। कहने को घोषित रूप से वाल्मी संस्था के आगे चंदनपुर, मेंडोरा आदि का क्षेत्र टाइगर का विचरण इलाका है जहां वे तालाब पर पानी पीने भी आते हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात का तनिक भी भय नहीं था। दो दिन पहले ही सुबह की सैर के वक्त इसी इलाके में एक दंपत्ति के सामने टाइगर महाशय दहाड़ते हुए आये और उनकी ओर छलांग लगाई थी लेकिन अन्य लोगों के चीखने चिल्लाने पर वो पास के फार्म हाउस की झाड़ियों में ओझल हो गये थे। इस घटना का इन लोगों में कोई खौफ हो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। इस मार्ग पर घना जंगल है और बाघ विचरण क्षेत्र के बोर्ड लगे होने पर भी यहां अनेक रिसॉर्ट, होटल्स, भवन, शिक्षण संस्थान, पौधों की नर्सरी आदि कब कैसे निर्मित हो गये कहा नहीं जा सकता। हाल ही एक मीडिया रिपोर्ट में आया था कि मेंडोरा गांव में एफटीएल और कैचमेंट एरिया में कथित तौर पर फार्म हाउस बेचे जा रहे हैं। नियमानुसार तो फॉरेस्ट एरिया में कोई भी निर्माण या गतिविधि नहीं चल सकती। खैर...

इस बाघ दिवस पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जंगल और जंगली जानवरों की रक्षा करना सभी का दायित्व है। जंगली जानवरों के क्षेत्र में घुसपैठ से परहेज कीजिये ताकि पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखने में बाधा उत्पन्न ना हो।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नया परीक्षा कानून

दुर्गेश्वर राय

लेखक शैक्षिक संवाद के संयोजक हैं।

क्या सुधार बचा पाएंगे युवाओं का भविष्य

देश के लाखों युवाओं के सपनों और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में परीक्षाओं की शुचिता वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत और संवेदनशील विषय बना हुआ है। हाल ही में नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुए पेपर लीक विवाद और उसके बाद भड़के राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलनों ने देश की परीक्षा प्रणाली की खामियों को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया। इन व्यापक विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए दबाव के बीच तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का नया कार्यभार संभाला है। छात्रों के इस आक्रोश ने स्पष्ट कर दिया कि केवल कागजी कानून से काम नहीं चलने वाला हैं। इन कानूनों के कठोरता से क्रियान्वयन और व्यवस्था में आमूलचूल तकनीकी सुधार करना ही होगा। इसी पृष्ठभूमि में, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और छात्रों का खोया हुआ विश्वास बहाल करने के लिए प्रशासनिक और विधायी स्तर पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें हालिया संशोधन विधेयक और एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन प्रमुख है।

इस नई व्यवस्था की आवश्यकता को समझने के लिए इसके मूल कानून, 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024' पर दृष्टि डालना आवश्यक है। फरवरी 2024 में पारित इस कानून का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना था। उस कानून में परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से गड़बड़ी करने वालों के लिए तीन से पांच साल की सजा और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था, जबकि संगठित माफिया या संस्थागत संलिप्तता के मामले में पांच से दस साल की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, वर्तमान में देश भर में हुए आंदोलनों ने यह साबित कर दिया कि ये सजाएं संगठित अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त निवारक नहीं बन सकीं। यही कारण है कि नए संशोधन विधेयक के माध्यम से इन दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि शिक्षा माफियाओं के भीतर कानून का वास्तविक भय पैदा किया जा सके और मुकदमों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।

विधायी सख्ती के साथ-साथ, परीक्षा प्रणाली की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ठोस प्रशासनिक कदम भी उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लीक-प्रूफ और तकनीक-संचालित बनाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण समिति का नेतृत्व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष व इन्फोसिस के सह-संस्थापक और प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। यह एक बहु-विषयक समिति है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे अनुभवी दिग्गज शामिल हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य जोर विशेष रूप से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा प्रणाली को तकनीकी दृष्टिकोण से सुधारने और पुनर्गठित करने पर होगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि हमारी परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी हो, तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए। हालांकि, राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे केवल प्रधानमंत्री की छवि सुधारने का एक प्रयास करार दिया है।

अब यह यक्ष प्रश्न उठता है कि क्या ये नए कदम और विधेयक वास्तव में सुचिता पूर्ण परीक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा करोड़ों युवाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक उत्थान का एकमात्र साधन है, वहां ऐसे सख्त कानूनों और तकनीकी सुधारों का महत्व अत्यधिक है। एक त्रुटिहीन परीक्षा प्रणाली न केवल योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी सही प्रतिभाओं का योगदान सुनिश्चित करती है। नंदन नीलेकणी जैसे विशेषज्ञ के नेतृत्व में तकनीक का एकीकरण और नए विधेयक के सख्त दंडात्मक प्रावधान मिलकर एक ऐसा मजबूत तंत्र विकसित कर सकते हैं, जिसे भेद पाना संगठित माफियाओं के लिए लगभग असंभव हो जाए। इस पूरी कवायद की सफलता पूरी तरह से इसके जमीनी क्रियान्वयन और व्यवस्था में बैठे लोगों की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करेगी। यदि इन सुधारों को इनकी सच्ची भावना के साथ लागू किया गया, तो यह निश्चित रूप से देश के मेहनती युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

गुरु पूर्णिमा

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

भगवा ध्वज से गुरु दक्षिणा तक समर्पण, संस्कार और राष्ट्रसेवा

भारत की सनातन परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और संकीर्णता से व्यापकता की ओर मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। इसी गुरु-परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है–गुरु पूर्णिमा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से भी गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन, समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रकार्य के प्रति पुनः संकल्प लेने का अवसर है। संघ में व्यक्ति-पूजा के स्थान पर आदर्श, विचार और राष्ट्र को सर्वोच्च माना गया है। इसी कारण संघ ने अपने गुरु के रूप में किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि भगवा ध्वज को स्वीकार किया है।

भगवा ध्वज भारतीय त्याग, तपस्या, ज्ञान, शौर्य और समर्पण का प्रतीक है। संघ के स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसी भगवा ध्वज के समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और अपने जीवन, समय, सामर्थ्य तथा अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्रकार्य में योगदान का संकल्प लेते हैं। संघ के इतिहास में गुरु पूर्णिमा का विशेष स्थान है। संघ के आधिकारिक इतिहास के अनुसार 1928 में पहली बार गुरुपूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इसी कालखंड में संघ की कार्यपद्धति में गुरु दक्षिणा की परंपरा का भी प्रारंभ हुआ। प्रथम गुरु दक्षिणा उत्सव में कुल 84 रुपये का समर्पण हुआ था। यह राशि अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए नहीं थी कि वह कितनी थी, बल्कि इसलिए कि उसने संघ के आर्थिक स्वावलंबन और स्वयंसेवक के व्यक्तिगत समर्पण की एक विशिष्ट परंपरा की नींव रखी।

संघ की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में ही यह स्पष्ट हो गया था कि संगठन का संचालन बाहरी आर्थिक सहायता पर निर्भर न होकर स्वयंसेवकों के स्वैच्छिक योगदान और समर्पण से होना चाहिए। गुरु दक्षिणा इसी भाव का प्रतीक बनी।

इस प्रकार गुरु पूर्णिमा संघ के लिए तीन प्रमुख भावों का पर्व बन गई–श्रद्धा, भगवा ध्वज के प्रति; समर्पण, राष्ट्र और समाज के प्रति; और संकल्प, स्वयं के चरित्र निर्माण तथा राष्ट्रसेवा के प्रति। संघ का गुरु कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है कि उसने किसी व्यक्ति को अपना गुरु नहीं माना। संघ ने भगवा ध्वज को गुरु स्वीकार किया है।

इसका गहरा दार्शनिक अर्थ है। व्यक्ति परिवर्तनशील है। व्यक्ति का जीवन सीमित है। लेकिन विचार, आदर्श और राष्ट्र का जीवन दीर्घकालीन होता है। इसलिए संघ ने अपने गुरु के रूप में ऐसे प्रतीक को स्वीकार किया, जो भारतीय संस्कृति के हजारों वर्षों के त्याग, तपस्या, ज्ञान और राष्ट्रधर्म का प्रतिनिधित्व करता है। भगवा ध्वज स्वयंसेवक को यह स्मरण कराता है कि संगठन में व्यक्ति नहीं, ध्येय सर्वोपरि है।

संघ के सरसंघचालक भी स्वयं को गुरु नहीं मानते। वे संघ के कार्य का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं। यही कारण है कि संघ में गुरु दक्षिणा किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि भगवा ध्वज के माध्यम से उस महान राष्ट्रीय ध्येय को अर्पित की जाती है, जिसके लिए स्वयंसेवक काम करता है। गुरु दक्षिणा केवल धन का समर्पण नहीं सामान्य अर्थों में गुरु दक्षिणा का अर्थ गुरु को धन या वस्तु अर्पित करना माना जाता है। लेकिन संघ की परंपरा में गुरु दक्षिणा का अर्थ इससे कहीं व्यापक है।

यह स्वयंसेवक के जीवन में समर्पण की भावना को जागृत करने का माध्यम है। स्वयंसेवक अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा अर्पित करता है। इसमें राशि का बड़ा या छोटा होना मुख्य नहीं है। मुख्य बात यह है कि स्वयंसेवक अपने परिश्रम से अर्जित धन में से राष्ट्रकार्य के लिए स्वेच्छा से कुछ अंश समर्पित करता है। इसलिए गुरु दक्षिणा को संघ की आर्थिक स्वावलंबन की परंपरा के साथ-साथ आत्मसमर्पण की साधना भी कहा जा सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन संघ में कार्यक्रम कैसे होता है? संघ की स्थानीय परंपराओं और परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम के स्वरूप में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्यतः गुरु पूर्णिमा अथवा गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भगवा ध्वज के समक्ष स्वयंसेवक एकत्रित होते हैं। ध्वज प्रणाम किया जाता है। स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर प्रणाम करते हैं। यह व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि आदर्श और ध्येय के प्रति नमन होता है।

इसके बाद संघ प्रार्थना होती है। सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से राष्ट्र, समाज और संगठन के प्रति स्वयंसेवक अपने संकल्प को पुनः स्मरण करता है।

कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ता अथवा संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता गुरु पूर्णिमा, भारतीय गुरु-परंपरा, संघ के ध्येय और वर्तमान सामाजिक चुनौतियों पर विचार रखते हैं।

इसके बाद गुरु दक्षिणा समर्पण का कार्यक्रम होता है। स्वयंसेवक अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा अर्पित करता है। यह समर्पण सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से और स्वैच्छिक भाव से किया जाता है। गुरु दक्षिणा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आत्ममंथन। स्वयंसेवक स्वयं से प्रश्न करता है–मैंने राष्ट्र के लिए क्या किया और आगे क्या करना है? इस अवसर पर स्वयंसेवक अपने जीवन में अधिक समय, अधिक अनुशासन, अधिक सेवा और अधिक सामाजिक सक्रियता का संकल्प लेता है।

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार : संगठन ही साधना संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने संगठन को व्यक्ति-निर्माण की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया। उनके लिए संघ का लक्ष्य केवल शाखा चलाना नहीं था, बल्कि ऐसे स्वयंसेवक तैयार करना था जो समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन जी सकें। गुरु पूर्णिमा की दृष्टि से डॉ. हेडगेवार की कार्यपद्धति का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही था कि राष्ट्रकार्य किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति का परिणाम होना चाहिए। उन्होंने संघ को व्यक्ति-केंद्रित न बनाकर ध्येय-केंद्रित बनाया। आगे चलकर भगवा ध्वज को गुरु स्वीकार करने की परंपरा इसी दृष्टि को मजबूत करती है।

श्री माधव सदाशिव गोलवलकर 'श्री गुरुजी' : व्यक्ति नहीं, तत्व महत्वपूर्ण दूसरे सरसंघचालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें संघ परिवार में स्नेहपूर्वक 'श्री गुरुजी' कहा जाता है, ने स्वयंसेवक के चरित्र, अनुशासन और आत्मीयता पर विशेष बल दिया। उनके विचारों में स्वयंसेवक केवल शाखा में उपस्थित रहने वाला व्यक्ति नहीं है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार, व्यवसाय और सामाजिक व्यवहार में भी संघ के संस्कारों को अभिव्यक्त करता है। गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में श्री गुरुजी की दृष्टि का सार यह कहा जा सकता है कि गुरु दक्षिणा केवल धन देना नहीं, बल्कि अपने जीवन को ध्येय के अनुकूल बनाने की साधना है।

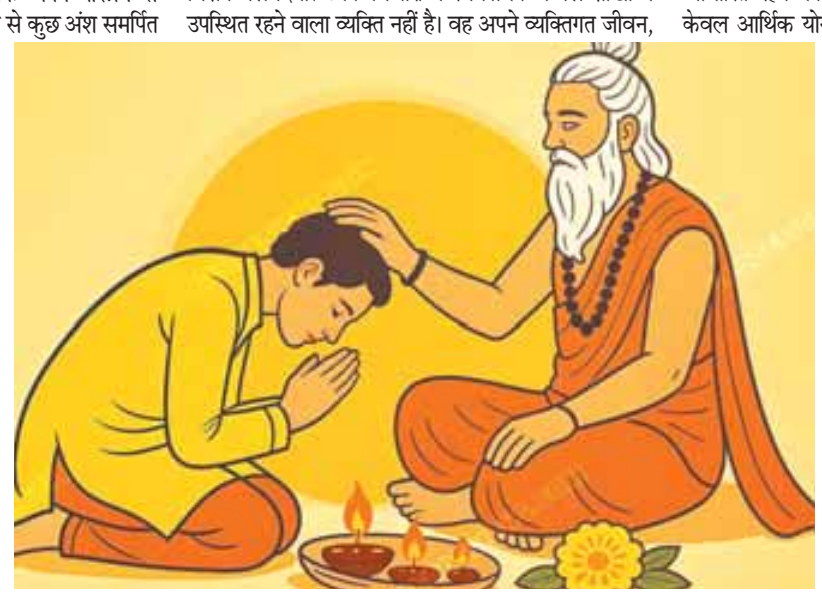

बालासाहब देवरस : सामाजिक परिवर्तन का संकल्प तीसरे सरसंघचालक बालासाहब देवरस ने संघ के कार्य को सामाजिक समरसता और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा। उनकी दृष्टि में समाज की एकता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि व्यवहार में समानता, आत्मीयता और सामाजिक सहभागिता से स्थापित होगी। गुरु पूर्णिमा का अवसर स्वयंसेवक को यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है–क्या मेरा समर्पण केवल संगठन तक सीमित है या समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंच रहा है? इस दृष्टि से गुरु दक्षिणा का अर्थ सेवा, सामाजिक समरसता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार करना भी है।

प्रो. राजेंद्र सिंह 'रज्जू भैया' : सरलता और आत्मीयता चौथे सरसंघचालक प्रो. राजेंद्र सिंह 'रज्जू भैया' अपने सरल व्यक्तित्व और आत्मीय व्यवहार के लिए जाने जाते थे।

उनके जीवन में गुरु-परंपरा का अर्थ था–ज्ञान, विनम्रता और सेवा। गुरु पूर्णिमा का संदेश उनके जीवन से यह मिलता है कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है, जब वह समाज के काम आए। इसलिए स्वयंसेवक का जीवन जितना सरल होगा, उतना ही वह समाज के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकेगा।

कुप्प. सी. सुदर्शन : स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पांचवें सरसंघचालक कुप्प. सी. सुदर्शन ने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और भारतीय चिंतन पर विशेष बल दिया। गुरु दक्षिणा की परंपरा में भी आत्मनिर्भरता का यही तत्व दिखाई देता है। संघ का संगठन अपने कार्य के लिए स्वयंसेवकों के स्वैच्छिक योगदान पर आधारित रहने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से गुरु दक्षिणा केवल आर्थिक योगदान नहीं, बल्कि 'हम अपने ध्येय के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं'–इस भाव की अभिव्यक्ति है।

डॉ. मोहन भागवत : स्वयंसेवक से समाज तक वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने संघ के कार्य को व्यक्ति निर्माण, सामाजिक सहभागिता और राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए अनेक अवसरों पर स्वयंसेवक के व्यापक दायित्व की चर्चा की है। उनकी दृष्टि में संघ का कार्य केवल शाखा के एक घंटे तक सीमित नहीं है; स्वयंसेवक के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक और आजीविका से जुड़े शेष जीवन में भी संघ के संस्कारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का भी मूल संदेश यही है–समर्पण के साथ आत्ममंथन।

प्रचारक : गुरु दक्षिणा की जीवंत प्रतिमूर्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति में प्रचारकों का विशेष महत्व है। प्रचारक वह स्वयंसेवक है जो अपने व्यक्तिगत जीवन की सुविधाओं को पीछे रखकर संघकार्य और समाजकार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। यदि गुरु दक्षिणा को केवल आर्थिक समर्पण के रूप में देखा जाए तो उसका अर्थ सीमित हो जाएगा। संघ के प्रचारक का जीवन इस परंपरा के व्यापक अर्थ को सामने रखता है। प्रचारक अपने जीवन का सबसे मूल्यवान धन–अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान और अपना अनुभव–समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करता है। इस दृष्टि से प्रचारक का जीवन स्वयं में एक प्रकार की जीवंत गुरु दक्षिणा है।

गुरु पूर्णिमा : स्वयंसेवक के लिए आत्ममंथन का दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संघ का स्वयंसेवक केवल यह नहीं सोचता कि उसने गुरु दक्षिणा में कितनी राशि दी। वह यह भी विचार करता है–मैंने समाज के लिए कितना समय दिया? मैंने कितने लोगों को जोड़ा? क्या मेरे व्यवहार में सेवा और आत्मीयता दिखाई देती है? क्या मैं समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हूँ? क्या मैं अपने परिवार और व्यवसाय के साथ राष्ट्र के प्रति भी अपना दायित्व निभा रहा हूँ? यही कारण है कि गुरु दक्षिणा को संघ की दृष्टि से एक प्रकार का वार्षिक आत्मपरीक्षण भी माना जा सकता है।

गुरु दक्षिणा : संघ की आर्थिक स्वावलंबन की आधारशिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति में गुरु दक्षिणा का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। किसी भी संगठन को अपने कार्यों के संचालन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संघ ने अपने कार्य के लिए स्वयंसेवकों के स्वैच्छिक योगदान को महत्व दिया। इससे दो बातें सुनिश्चित होती हैं–पहली, संगठन अपने कार्य के लिए समाज और स्वयंसेवकों के सहयोग पर आधारित रहता है। दूसरी, स्वयंसेवक को यह अनुभव होता है कि वह केवल संगठन का सदस्य नहीं, बल्कि उसके कार्य का सहभागी और उत्तरदायी घटक है। इस अर्थ में गुरु दक्षिणा आर्थिक स्वावलंबन और संगठनात्मक सहभागिता–दोनों का माध्यम बनती है।

गुरु पूर्णिमा और संघ : परंपरा से आधुनिकता तक आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, तकनीक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन रही है और व्यक्तिगत जीवन अधिक व्यस्त हो रहा है, तब गुरु पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का नाम नहीं है। व्यक्ति की सफलता तभी सार्थक है, जब वह समाज के लिए उपयोगी बने। आज की परिस्थितियों में गुरु पूर्णिमा का संदेश और भी व्यापक हो जाता है– ज्ञान मिले तो विनम्रता आए। सामर्थ्य मिले तो सेवा बढ़े। सफलता मिले तो समाज का स्मरण रहे। और जीवन मिले तो राष्ट्र के काम आए।

निष्कर्ष : गुरु दक्षिणा से राष्ट्र दक्षिणा तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए गुरु पूर्णिमा केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है। यह एक ऐसी परंपरा है, जो स्वयंसेवक को अपने जीवन का मूल्यांकन करने और अपने ध्येय के प्रति पुनः समर्पित होने का अवसर देती है। भगवा ध्वज के समक्ष अर्पित गुरु दक्षिणा वस्तुतः एक प्रतीक है–उस महान भारतीय परंपरा के प्रति श्रद्धा का, जिसने त्याग और तपस्या को जीवन का आदर्श माना। संघ के लिए गुरु व्यक्ति नहीं, ध्येय है। गुरु दक्षिणा धन नहीं, समर्पण है। शाखा केवल कार्यक्रम नहीं, व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला है। प्रचारक केवल कार्यकर्ता नहीं, समर्पित जीवन का उदाहरण है। और स्वयंसेवक केवल संगठन का सदस्य नहीं, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश यही है कि हम अपने जीवन में किसी महान आदर्श को स्थान दें और उस आदर्श के प्रति अपने समय, श्रम, प्रतिभा और सामर्थ्य को समर्पित करें।

भगवा ध्वज के समक्ष झुकता हुआ स्वयंसेवक वस्तुतः अपने अहंकार को झुकाता है। गुरु दक्षिणा में अर्पित धन केवल मुद्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। और जब यह श्रद्धा सेवा में बदलती है, सेवा समर्पण में बदलती है और समर्पण राष्ट्रनिर्माण में बदलता है–तभी गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ साकार होता है।

यही गुरु पूर्णिमा है।
यही गुरु दक्षिणा है।
और यही राष्ट्रकार्य की साधना है।

गुरु पूर्णिमा विशेष

अस्मिता सिंह
लेखक शोधार्थी हैं।

यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान

हमारे देश का जीवन-दर्शन सदैव संतुलन और समन्वय का दर्शन रहा है। यहाँ शिक्षा और विद्या के साथ योग और भोग, भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक चेतना, शरीर के साथ आत्मा तथा प्रकृति के साथ परमात्मा का संतुलित संबंध स्थापित किया गया। भारतीय संस्कृति ने सदैव ज्ञान को ही सर्वोच्च शक्ति माना है; इसलिए हमारी संस्कृति ज्ञान के प्रकाश की उपासक रही है। हमारे यहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान, विवेक, संस्कार और आत्मबोध की प्रतिष्ठा की गई। इस ज्ञान परंपरा के केंद्र में सदैव गुरु रहे हैं, जिन्होंने मनुष्य को जीवन जीने की कला, प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और लोकमंगल का मार्ग दिखाया। वैदिक काल से लेकर उपनिषदों, बौद्ध परंपरा, नाथ संप्रदाय, भक्ति आंदोलन और आधुनिक भारत तक गुरु को जीवन का निर्माता माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद का 'आचार्य देवो भव:' यह प्रकट करता है कि गुरु ही मनुष्य के व्यक्तित्व को संस्कारित कर समाज और राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला रखता है।

संत कबीर के गुरु ईश्वर से बढ़कर हो गए क्योंकि वे आत्मबोध का मार्ग दिखते है। कबीर हो या अन्य संत सभी नाना प्रकार की उपमा गुरु को देते हुए सम्मान प्रकट करते है। दरअसल भारतीय परंपरा में गुरु को व्यक्ति नहीं एक तत्त्व माना गया है। एक ऐसा तत्व जो जीवन को दिशा देता है, चेतना को परिष्कृत करता है और मनुष्य को उसके सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुँचाने का कार्य करता है। यह तत्व प्रकृति से तादात्म्य रखता है। इसीलिए हम वृक्ष में भी गुरु के इसी स्वरूप का दर्शन करते है।

अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु और वृक्ष के बीच प्रगाढ़ संबंध देखे गए है। नाथ संप्रदाय की अवधूत परंपरा में कहा गया है- 'वृक्ष मेरा स्वरूप है।' यह कथन वृक्ष के निस्वार्थ, धैर्यवान और लोककल्याणकारी स्वरूप को गुरु के गुणों से जोड़ता है। दत्त संप्रदाय में गूलर वृक्ष के मूल में भगवान दत्तात्रेय को विराजमान माना गया हैं, जो भक्तों को ज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रदान करते है। वैदिक और सनातन परंपरा में पीपल, वट, अशोक, बेल, तुलसी और आंवले जैसे वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को गया में पीपल (बोधि) वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह वृक्ष आज भी पूजनीय है। जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थंकर का ज्ञान या कैवल्य प्राप्ति एक विशिष्ट वृक्ष से जुड़ा माना गया है, जिससे वृक्ष आध्यात्मिक चेतना और मोक्ष के साक्षी बनते हैं। वहीं सिख परंपरा में भी अनेक ऐतिहासिक वृक्ष गुरुओं की तपस्या, प्रवचन और संगत के कारण श्रद्धा के केंद्र हैं। भारतीय संस्कृति का यह संबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा का आरंभ वनों से हुआ। ऋषि-मुनियों ने अपने आश्रम नगरों में नहीं, तपोवनों, अरण्यों और नदी तटों पर स्थापित किए। सांदीपनि आश्रम, नैमिषारण्य, दंडकारण्य, कण्वाश्रम, वाल्मीकि आश्रम, गंगा और नर्मदा के तट ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के विश्वविद्यालय थे। वहाँ वृक्ष पाठशाला और शिक्षक के सहचर थे। प्रकृति स्वयं पाठ्यपुस्तक थी और वन जीवन का विश्वविद्यालय।

भारतीय संस्कृति ने गुरु और वृक्ष दोनों को पूजनीय माना क्योंकि दोनों देने की संस्कृति के प्रतीक हैं। वृक्ष कभी अपनी छाया का मूल्य नहीं माँगता और गुरु कभी अपने ज्ञान का प्रतिदान नहीं चाहता। दोनों का अस्तित्व परोपकार पर आधारित है। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- 'अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणाम्', अर्थात् वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यह कथन प्रकृति के प्रति सम्मान का सांस्कृतिक संदेश है।

आज विडंबना यह है कि जैसे समाज में गुरु का स्थान चुनौती के दौर से गुजर रहा है, वैसे ही वृक्ष और वन भी संकट में हैं। ज्ञान की जगह सूचना ने, संस्कार की जगह प्रतिस्पर्धा ने और प्रकृति की जगह कंक्रीट ने ले ली है। परिणाम हमारे सामने हैं। हमने गुरु से सीखने की परंपरा भी कमजोर की और प्रकृति से सीखने की संस्कृति भी।

ऐसे समय में मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चलाया गया 'एक गुरु-एक वृक्ष' अभियान भारतीय परंपरा को वर्तमान से जोड़ने का सार्थक प्रयास है जिसमें अब तक विद्यार्थियों ने 40 हजार से भी अधिक पौधे लगाए। जब विद्यार्थी अपने गुरु के सम्मान में एक वृक्ष लगाते हैं, तो वे यह संकल्प लेते हैं कि ज्ञान की तरह प्रकृति भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी संरक्षित रहेगी।

सबसे बड़ा गुरु स्वयं प्रकृति है। कबीर का दोहा आज पहले से अधिक प्रासंगिक है। यदि गुरु अमृत का स्रोत है, तो वृक्ष उस अमृत का विस्तार हैं। गुरु जीवन को संस्कारित करता है और वृक्ष पृथ्वी को। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर गुरु को प्रणाम करने का सबसे सार्थक तरीका एक वृक्ष लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेना भी हो सकता है। क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे शब्दों से नहीं, उन वृक्षों की छाया से भी हमें याद रखेंगी, जिन्हें हमने उनके लिए बचाया होगा।

गुरु पूर्णिमा विशेष

डॉ. लोकेन्द्रसिंह कोट
लेखक स्तंभकार हैं।

गुरु की कृपा प्राप्त होने पर मुक्त होता है जीवन

सनातन वैदिक संस्कृति तथा जीवन पद्धति की समृद्ध परम्परा में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु में दो अक्षर हैं 'गु' जिसका अर्थ है अंधकार तथा 'रु' का अर्थ है प्रकाश! अर्थात् गुरु वह तत्व है जो अन्धकार को मिटाता है और प्रकाश को फैलाता है। अज्ञान को मिटाता है और ज्ञान की ज्योति को जलाता है, इसी गुरु को प्रणाम करते हुए शिष्य कहता है-

अज्ञान तिमिरोधस्य ज्ञानाजनं शलाकया।
चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः॥

गुरु वह ऊर्जावान, प्रज्ञावान महापुरुष है जो शिष्य की आंख में ज्ञान के अंजन की शलाका से अज्ञान के अन्धकार को दूर करते हैं और शिष्य के जीवन को धन्य करते हैं। किसी विद्वान ने अपने उद्बोधन में ही कहा है कि जाओ और गुरूजन की वाणी सुनो तथा उसे अपने हृदय में धारण करो जिससे जब तुम वापस आओ जो कोई नई वस्तु अपने साथ ला सको। 'श्रीरामचरित मानस' में आता है,

गुरु बिन भव निधि तरइ न कोई ।
जौ बिरंचि संकर सम होई ।।

'गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहें वह ब्रह्माजी और शंकरजी के समान ही क्यों न हो!' सदगुरु का अर्थ शिक्षक या आचार्य नहीं है । शिक्षक अथवा आचार्य हमें थोड़ा-बहुत ऐहिक ज्ञान देते हैं लेकिन सदगुरु तो हमें निजस्वरूप का ज्ञान दे देते हैं । जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह उत्पन्न न हो, दुःख का प्रभाव न पड़े और परब्रह्म की प्राप्ति हो जाए ऐसा ज्ञान गुरुकृपा से ही मिलता है । गुरू के बगैर व्यक्ति को प्राचीन काल में निगुरा या अनाथ कहा जाता था।

'सच्चे गुरु वे हैं, जिनके द्वारा हमको अपना आध्यात्मिक जन्म प्राप्त हुआ है। वे ही वह साधक हैं, जिसमें से होकर आध्यात्मिक प्रवाह हम लोगों में प्रवाहित होता है। वे ही समग्र आध्यात्मिक जगत के साथ हम लोगों के संयोग सूत्र हैं। व्यक्ति विशेष पर अतिरिक्त विश्वास करने से दुर्बलता और अन्तः सार शून्य विधिः पूजा आ सकती है, किन्तु गुरु के प्रति प्रबल अनुराग से उन्नति अत्यन्त शीघ्र सम्भव है। वे हमारे अन्तः स्थित गुरु के साथ हमारा संयोग करा देते हैं।

एक ऐसा शिष्य गुरु के पास जाता है जो आशा विहीन है तो वह गुरु के संपर्क में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त कर अपनी आशा पूर्ण करता है। आज उसी एक गुरु की आवश्यकता है जो आत्मज्ञान कर सके उसके हर प्रश्न का उत्तर बन सके। इस तथ्य को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाए - शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया 'प्रकाश का स्त्रोत कहाँ है?' 'प्रकाश का स्त्रोत सूर्य है' - गुरुदेव का उत्तर था। 'और रात्रि में जब सूर्य नहीं होता तब?' 'तब प्रकाश का उत्स चन्द्रमा है।' 'अमावस्या की रात्रि में जब चन्द्रमा भी न हो, तब?' 'प्रकाश का आधार क्षीण बिन्दु तारे हैं।' 'वर्षा की रात्रि में जब तारे ही लुप्त हो जाए, तब?' 'तब दीपक का प्रकाश है।' 'झंझावात में दीपक भी बुझ जाए, तब?' 'तब प्रकाश का बिन्दु आत्मा में समाहित रहता है। आत्म-प्रकाश, आत्म-ज्ञान, प्रकाश का यह स्त्रोत अनश्वर व सर्वोपरि है। गुरुदेव का उत्तर सुनकर शिष्य जान गया कि 'जब घिर आए अंधकार सूझता न हो आर-पार, तब दीपक मन का जलाओ ज्योति की आशा जगाओ।'

आज हमें ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है जो हमारे मशीनी संस्करण में भी संवेदना फूँक सके, आत्म ज्ञान करा सके। आज हमारे सांस्कृतिक पतन के प्रमुख कारणों में एक यह भी महत्वपूर्ण कारण जुड़ गया है कि हमारे मध्य से वांछित गुरू गुम हो चुका है।

गुरु समाज का भी आईना है

गुरू का विहंगम रूप में अर्थ होता है कि समाज में उपस्थित एक प्रामाणिक प्रतिबिम्ब अर्थात किसी भी सांसारिक पहलू को परखने का मापदण्ड। प्रत्येक गुरु के व्यक्तित्व की मान्यताओं के आधार पर कुछ दृष्टि भेद स्वाभाविक हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट गुण-स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है परन्तु फिर भी विभिन्नता के मध्य एकत्व रहता है और यही ज्ञानवान होने का प्रमाण भी है। यही समाज को एक नवीन दिशा प्रदान करता है। आज के संदर्भों में देखा जाय तो यह प्रामाणिकता अब विरले ही दिखाई देती है। यही एक वजह है कि हमारे सभी के समक्ष आदर्शों का संकट है। आज के युवा आखिर किस दिशा में किस तरह और किसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति के अपने नियम हैं, कायदे हैं और वह उसी पर चलना पसंद करता है। वह अपने सिद्धांतों को ही कुतर्क के सहारे सही भी सिद्ध कर देता है। उसके कुतर्कों के लिए उसे उदाहरण भी बहुत मिल जाते हैं। विचारों में यह गिरावट का दौर पिछले दो दशकों से चल रहा है। तीक्ष्ण से तीक्ष्ण दिमाग भी बरगलाते हुए से दिखाई देते हैं। यह विडंबना ही है कि आज हमें यह बताने वाला गुरु विद्यमान नहीं है जो यह बता सके कि सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं है और मृगतृष्णा का कोई अंत नहीं है।

इस दौर में हमने यह भी महसूस किया है कि बुराई हमेशा सोने जैसे चमकीले छद्मावरण में ही सामने मिली है और लोगों ने उसे स्वर्ण समझ कर अपना लिया है। इस मुकाम पर हमें एक पारखी की आवश्यकता थी जो हमें बता सकता कि वास्तविक चमक क्या है।

गुरु अनुभव की खान

पुस्तकों से महज बिंदुवार अव्यवहारिक ज्ञान मिल सकता है तथा इसी तरह मशीनें भी कुछ हद तक पुस्तकों का सहज रूपान्तरण प्रस्तुत कर सकती हैं परन्तु व्यवहारिक और जमीनी सच्चाई तो किसी के अनुभव से ही मिल सकती है। यह जीवनानुभव गुरु से ही मिल सकता है। एक मशीन एक नदी की औसत गहराई तीन फीट बता सकती है परन्तु नदी की गहराई हर जगह थोड़े ही तीन फीट होगी। यह बात तो अनुभवी गुरु से ही मिल सकती है, इसके अभाव में डूबना तो स्वाभाविक है ही।

प्रकृति की प्रत्येक वस्तु और वे सारी अच्छी-बुरी घटनाएँ जो हमारे या दूसरे के जीवन में घटती है, वे सभी हमारी गुरू साबित हो सकती हैं, बशर्ते हम उन पर ध्यान दें। एक गलती में से यथार्थ को खोजकर यदि मूल बात का ज्ञान हमें हो जाय तो हो सकता है हम अगली बार गलती को दोहराएँगे नहीं। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किस ढ़ंग से हुआ है, हममें अच्छे-बुरे की पहचानने की क्षमता है भी कि नहीं और हम कितने संवेदनशील हैं। ज्ञान में से भी ज्ञान उतारने के लिए एक अच्छे गुरू की आवष्यकता होती है, वरना वह अर्थ का अनर्थ भी निकाल सकता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के उपदेश में कहा है कि, 'उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली-भाती दण्डवत् प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रष्न करने से सभी कुछ जानने वाले गुरू तुझे वे सारे उत्तर देंगे, जो तू चाहता है।'

अब यदि हमें असली ज्ञान की चाह है तो उसके लिए कठोर मेहनत के संस्कारों की नींव फिर से डालनी होगी क्योंकि सूर्य की किरणों के आनन्द लेने के लिए हम यह तो नहीं सोच सकते कि किरणें स्वयं दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगी, इसके लिए हमें बाहर जाना होगा। यही गुरू की महिमा है और तभी कहा भी गया है कि, 'गुरु बिनु होइ कि ज्ञान।'

ध्यान मूलं गुरूमूर्तिं पूजा मूलं गुरोर्रपदम।
मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा॥

ध्यान में गुरु का स्वरूप, पूजा गुरु चरणों की, गुरु का वाक्य या निर्देश ही जीवन का मन्त्र होता है तो गुरु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन मुक्त होता है, आनन्द की सृष्टि होती है। यही जब जीवन का ध्येय बनता है।

क्लॉक टावर और रेडस्टोन से होगा लल्ली चौक का सौंदर्यीकरण

नगर पालिका भवन को मिलेगा हेरिटेज लुक, सीएमओ ने अधिकारियों के साथ किया स्थल निरीक्षण

बैतूल। शहर के प्रमुख लल्ली चौक और नगर पालिका परिसर का सौंदर्यीकरण इस सप्ताह से शुरू होगा। विधायक एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश, कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे और नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर के मार्गदर्शन तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पाण्डेय के नेतृत्व में यह परियोजना अमल में लाई जाएगी। सोमवार को सीएमओ नवनीत पाण्डेय ने अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। सीएमओ नवनीत पाण्डेय ने बताया कि योजना के अनुसार लल्ली चौक पर लगभग 15 फीट ऊंचा क्लॉक टावर स्थापित किया जाएगा, वहीं जय स्तंभ परिसर का रेड स्टोन से सौंदर्यीकरण कर उसके चारों ओर करीब दो फीट ऊंची आकर्षक बाउंड्री बनाई जाएगी। हाल ही में हटाए गए अतिक्रमण वाले हिस्से में मिट्टी भरकर दीवार बनाई जाएगी और हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण किया जाएगा। भविष्य में मिसाइल मॉडल सहित अन्य आकर्षक संरचनाएं भी विकसित करने की योजना है। यातायात को सुगम बनाने के

लिए वर्तमान गोल चौराहे (रोटरी) को पीछे की ओर स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी और वाहनों की आवाजाही आसान होगी। आवश्यकता पडने पर हाईमास्ट पोल को भी बाउंड्री के भीतर नए स्थान पर स्थापित किया जाएगा। कारगिल चौक की ओर सडक चौड़ीकरण का कार्य बारिश के बाद शुरू किया जाएगा, जहां लगभग 80 एमएम मोटाई के ब्लॉक लगाने की भी योजना है। इसके साथ ही नगर पालिका के पुराने भवन का भी कायाकल्प किया जाएगा। भवन की मूल ऐतिहासिक संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे हेरिटेज लुक दिया जाएगा। पुराने स्ट्रक्चर पर पीवीसी पैनल लगाए जाएंगे, जिससे भवन संग्रहालय जैसा दिखाई देगा। साथ ही ग्लास बोर्ड लगाकर बैतूल जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। सीएमओ ने बताया कि यह पूरा विकास कार्य शहर को नई पहचान देने और नागरिकों को बेहतर यातायात व आकर्षक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई, उत्कृष्ट अंक प्राप्त होने वाले छात्र छात्राओं को किया सम्मानित

सोहागपुर। संस्कार गार्डन में प्रजापति कुंभकार समाज ने दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। जयंती प्रदेश उपाध्यक्ष जशराज प्रजापति, जिला प्रजापति कुंभकार समाज अध्यक्ष चतुर्भुज प्रजापति, तहसील प्रजापति कुंभकार समाज अध्यक्ष कमलेश प्रजापति, पिपरिया प्रजापति कुंभकार समाज अध्यक्ष मदन प्रजापति आदि के आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस

अवसर पर भगवान दक्ष प्रजापति महराज की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत प्रजापति समाज के कक्षा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान करके उत्साहवर्धक किया गया। इसी क्रम में शासकीय सेवा में कार्यरत एवं सेवा निवृत्त सामाजिक बंधुओं एवं मूर्ति कला में पारंगत सामाजिक बंधुओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन कमलेश प्रजापति किया। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित करके समाज के लिए सर्मपण करने का आव्हान किया गया। कार्यक्रम में आस-पास के क्षेत्रों भारी संख्या में नागरिकों एवं मातृशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंत सभी का आभार व्यक्त किया गया।

कतिया समाज भुजरिया उत्सव धूमधाम से मनाएगी

सोहागपुर। श्री भूरा भगत जन जागृति समाज की बैठक समाज के वरिष्ठ श्री रमेश सिंग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 6 सितंबर को भुजरिया का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जिसमें क्षेत्र के सजातीय बन्धुओं को आमंत्रित किया जाएगा।इसी दिन निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन तारीख की घोषणा की जाएगी।इसी बैठक में सामाजिक जनों श्री बी एल नायक ग्राम पोथियां , श्रीमति मुरली बाई महलगव आदि के निधन होने पर दो मिनिट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर रमेश सिंग, निरंजन देव आरसे, रमेश आरसे, मनमोहन चंद्रवंशी ,हरलाल बेलवंशी, रवीन्द्र बारसिया, श्रवण भन्नारिया,मुकेश कुमार लांझेश, अनिल बेलवंशी, पार्षद धर्मदास बेलवंशी, आयुष बारसिया अनिल जागवंशी, अजय आमरवंशी, नारायण लांझेश,श्र परमसुख पठारीया, मुकेश नायक, बलराम बेलवंशी, रामाधार नागेश(शिक्षक), कमलेश आमरवंशी आदि उपस्थित थे। श्री रवीन्द्र बारसिया ने आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर दी बधाई

बायोमेट्रिक आधारित प्री-ऑथराइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश की टीम तथा योजना से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का मध्यप्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएँ दीं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक (चिंतन शिविर) में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को 'बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट - हाइएस्ट प्री-ऑथराइजेशंस विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन' श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया।

बोरदेही थाना क्षेत्र में सज रही जुए की फड़, लग रहे दांव

आमला। बोरदेही थाना क्षेत्र में जुआ संचालित किया जा रहा है। जहां ग्रामीण सहित आस-पास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुँचकर जुए में लाखों के दांव लगा रहे है। क्षेत्र के जागरूक नागरिको ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र में दो स्थानों पर अलग-अलग जुआ संचालित किया जा रहा है। बताया जाता है कि इन जुआ घर पर दांव लगाकर जीत के चक्कर में ग्रामीण अपनी पूंजी गवां चुके है। यहां शराब पीकर उपद्रव करने की भी जानकारी सामने आ रही हैं। लेकिन पुलिस

कार्रवाही नहीं कर रही है। जो लोग जुआ खेलने जाते है। उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नही है, क्योंकि जुआ खिलाने वाले सुरक्षा की ग्यारंटी भी दे रहे है। जुआ घर बहुत दिनों से लगातार चल रहा है। जगह बदलकर, लेकिन अभी तक वँहा पुलिस की दस्तक ना होने से ग्यारंटी पर खिलाडियों को पूरा भरोसा हो गया है। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों व ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पुलिस इस जुआ घर को बंद कर अवैध गतिविधियों चलाने वालों पर कठोर कार्यवाई करें। इस संबंध में बोरदेही थाना प्रभारी राधेश्याम वट्टी का कहना है कि हरदौली में दबिश तो दी थी, पर वे लोकेशन चेंज कर लेते है। नदी नालों पर जहाँ कीचड़ है, ऐसी जगह खिलाते है। जल्द ही इन्हें पकडकर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 2027 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

बैतूल। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती बंदना जाट के मार्गदर्शन में जिला जनगणना हस्त पुस्तिका - 2027 को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिरहित ढंग से संपादित करने के उद्देश्य से 17 जुलाई से 28 जुलाई तक पीएमश्री शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल में जिले के समस्त चार्ज क्षेत्रों के क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के क्षेत्र पदाधिकारियों तथा चार्ज अधिकारियों को जिला जनगणना हस्त पुस्तिका तैयार करने की संपूर्ण कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इस दौरान विभिन्न प्रपत्रों के संधारण, आंकड़ों के संकलन एवं सत्यापन, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि तथा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप जानकारी तैयार करने संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनगणना कार्य निदेशालय, भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर भरतलाल गौर एवं शालिनी वर्मा द्वारा डीसीएचबी पोर्टल का व्यावहारिक प्रदर्शन करते हुए लॉगिन प्रक्रिया, ग्राम एवं नगरीय प्रोफाइल तैयार करने, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, प्रपत्रों के संधारण, डेटा सत्यापन, त्रुटि सुधार तथा अंतिम सबमिशन की प्रक्रिया का चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि जिला जनगणना हस्त पुस्तिका किसी जिले की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, सडक़, संचार, बैंकिंग, परिवहन, कृषि, पंचायत एवं नगरीय निकायों सहित सभी विषयों से संबंधित सूचनाओं का संकलन पूर्णत- प्रमाणिक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित होना आवश्यक है। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश- पालन करते हुए सभी आंकड़ों का भौतिक एवं डिजिटल स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा पोर्टल पर केवल शुद्ध एवं प्रमाणिक जानकारी ही दर्ज की जाए।

प्रशिक्षण में जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी सहित जिले के क्षेत्र पदाधिकारी उपस्थित रहे। तकनीकी सहयोग जिला जनगणना टीम द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। अंत में अधिकारियों ने सभी क्षेत्र पदाधिकारियों से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान का प्रभावी उपयोग करते हुए जिला जनगणना हस्त पुस्तिका (डीसीएचबी)-2027 का कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने का आह्वान किया।

उद्योग एवं स्वरोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी : कलेक्टर

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। व्यापार एवं उद्योग केंद्र की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभाग को हस्तांतरित नवीन भूमि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान डूडा बोरगांव एवं चोरपांडरा स्थित विभागीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों की जानकारी लेते हुए उनके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने तथा निवेश प्रस्तावों को शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला अंत्याव्यवसायी सहकारी विकास समिति की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों,

विशेष रूप से स्व-सहायता समूह की महिलाओं को अधिकाधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं में तेजी लाने, पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से लाभान्वित करने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

8 आईएएस अफसरों के तबादले

छतरपुर समेत 3 जिलों में नए कलेक्टर, मिशा सिंह की जगह शहडोल जाएंगे पार्थ जायसवाल

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मिशा सिंह की पोस्टिंग को लेकर किया गया है। दो दिन पहले जारी तबादला सूची में उन्हें शहडोल कलेक्टर बनाया गया था लेकिन अब संशोधित आदेश में उनकी पोस्टिंग अपर आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल कर दी गई है। मिशा सिंह प्रेग्नेंट हैं, इसी वजह से उन्होंने भोपाल या इंदौर में पदस्थापना का अनुरोध किया था।

इसके साथ ही पार्थ जायसवाल को छतरपुर से शहडोल कलेक्टर, मृणाल मीणा को बालाघाट से छतरपुर कलेक्टर और कुमार सत्यम को बालाघाट का नया कलेक्टर बनाया गया है। आदित्य गर्ग को मंदसौर कलेक्टर पद से हटाकर परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड बनाया गया है।

खाद्य, तकनीकी शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग में भी बदलाव- दिनेश जैन को अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से ओएसडी सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और अपर सचिव, उपभोक्ता संरक्षण विभाग बनाया गया है। गिरीश शर्मा परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग बने हैं।

वहीं, अंकित अस्थाना को उप सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है। उन्हें संचालक, कर्मचारी चयन मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

स्वरोचिष को सुशासन एवं नीति विश्लेषण का अतिरिक्त प्रभार- तबादला आदेश के मुताबिक, स्वरोचिष सोमवंशी को आगामी आदेश तक आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी के साथ सचिव, राज्य योजना आयोग तथा संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इससे पहले इस संस्थान के संचालक का अतिरिक्त प्रभार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग के पास था।

नशे से दूरी स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी : डॉ. ऋतु चौबे

बैतूल। युवाओं को नशे की लत से बचाकर स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से पंडित द्वारकादास महाविद्यालय, आठनेर में जंतु विज्ञान विभाग के तत्वावधान में नशे से दूरी है जरूरी विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से अवगत कराया तथा सभी ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पंडित द्वारकादास महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. ऋतु चौबे एवं संचालक आनंद राठौर की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते प्राचार्य डॉ. ऋतु चौबे ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे

से दूरी ही स्वस्थ और सफल जीवन की पहली सीढ़ी है। जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. चरण निरापुरे ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके परिवार, शिक्षा और भविष्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव डालता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, नशे से दूर रहने तथा समाज में सकारात्मक संदेश देने की अपील की। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। समापन अवसर पर प्रो. शिवदयाल अमरुते ने सभी विद्यार्थियों एवं उपस्थितजनों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। सभी ने स्वयं नशे से दूर रहने और समाज में नशामुक्ति का संदेश प्रसारित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. बी.आर. वंजारे ने किया।

एमपी की बड़ी व्यापारिक संस्था 'कैट' की नई टीम बनी

ग्वालियर के भूपेंद्र जैन फिर अध्यक्ष; इंदौर के रमेश गुप्ता महामंत्री बनाए

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय स्तर की व्यापारिक संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की मध्यप्रदेश की नई टीम की घोषणा की गई है। ग्वालियर के भूपेंद्र जैन फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि इंदौर के रमेश गुप्ता को महामंत्री बनाया गया। भोपाल जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया।

पिछले दिनों कैट की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके बाद नई

कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने घोषणा की। जिसमें अध्यक्ष जैन, महामंत्री जैन, प्रदेश मीडिया प्रभारी शर्मा बनाए गए। इसी तरह सुनील अग्रवाल भोपाल चैयरमैन, गोविंद असाटी छतरपुर संयुक्त अध्यक्ष, राजकुमार गुप्ता ग्वालियर प्रदेश संगठन महामंत्री बनाए गए।

कैट का भोपाल में प्रदेश कार्यालय है। नए अध्यक्ष जैन ने बताया कि व्यापारी एवं उद्योगपतियों के साथ मिलकर वे शासन से समन्वय बनाकर व्यापार को सुगम और सरल बनाने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में इजी ऑफ डूइंग विजनिस की भावना को मानते हुए सभी विभागों से आग्रह करेंगे कि वे भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में व्यापारी एवं उद्योगपतियों की मदद करें।

सांसद दर्शनसिंह चौधरी की क्षवि धूमिल करने का कुसंगत प्रयास, सोहागपुर में पुलिस को सौंपा ज्ञापन

सोहागपुर। फेसबुक पर 'शैलेन्द्र सिंह राजपूत' नामक प्रोफाइल से क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी के संबंध में अत्यंत आपत्तिजनक, भ्रामक एवं अमर्यादित पोस्ट विगत दिवस प्रकाशित की गई है। इस पोस्ट में उनके समर्थको में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध जिला भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल के पत्र में लिखित ज्ञापन सोहागपुर पुलिस थाने में एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में अंकित है कि सांसद दर्शन सिंह चौधरी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि 'दर्शन चौधरी आपके जहां भी मिले उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए इस दुनिया में अब नहीं रहे..' 'ऊँ शांति, ओम शांति' लिखी हुई तस्वीर लगाकर सांसद जी का चित्र प्रदर्शित करके उनके फेसबुक अकाउंट को टैग किया गया है।उक्त

पोस्ट का स्वरूप स्पष्ट रूप से ऐसा है।कि जिससे आमजन में यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि सांसद दर्शनसिंह चौधरी का निधन हो गया है। सांसद जी पूर्णतः सक्रिय हैं तथा जनता के बीच जनसेवा एवं विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के संबंध में इस प्रकार मृत्यु एवं अंतिम संस्कार से संबंधित भ्रामक सामग्री प्रकाशित करना अत्यंत गंभीर एवं निंदनीय कृत्य है। इससे सांसद जी की सामाजिक एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है। इससे उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। तथा अनावश्यक भ्रम एवं मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो रही है। उक्त कृत्य सामान्य राजनीतिक आलोचना अथवा वैचारिक विरोध की सीमा से पूर्णतः परे हैं। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के संबंध में उसकी मृत्यु का झूठा भ्रामक चित्रण करना तथा अंतिम संस्कार की सामग्री प्रकाशित करना गंभीर विषय है। इस कारण उक्त फेसबुक प्रोफाइल एवं पोस्ट की तत्काल जांच कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। उक्त ज्ञापन का वाचन वकील शिवकुमार पटेल ने करके पुलिस को सौंपा।इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष जालमसिंह पटेल, उपाध्यक्ष राघवेंद्र पटेल,अधिवक्ता शिवकुमार पटेल, विजेंद्र ठाकुर, विक्रांत चौरसिया, शरद चौरसिया, बहादुर पटेल, नर्मदा प्रसाद कुशवाहा, अमन साहू, अनिल साहू आदि उपस्थित थे। उक्त आश्य की जानकारी अधिवक्ता शिवकुमार पटेल ने इस प्रतिनिधि को दी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा की।

खरगोन में 41.58 लाख रुपये का बैंक गबन

फरार शाखा प्रबंधक राजेश राठौर गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

खरगोन (नप्र)। जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठीबगांव शाखा में 41.58 लाख रुपये के गबन के मामले में फरार चल रहे शाखा प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूर्व से गिरफ्तार मुख्य आरोपी बैंक कैशियर रितु गोयल ने गबन की ज्यादातर राशि ऑनलाइन गेमिंग और अपने परिवार को हवाई यात्रा करने में खर्च कर दी थी।

जैतापुर थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया ने बताया कि फरार शाखा प्रबंधक राजेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह 41 लाख 58 हजार 95 रुपये के गबन के मामले में आरोपी बनाया गया था। उन्होंने बताया कि 25 मई को डीसीसीबी की ठीबगांव शाखा की कैशियर रितु गोयल अचानक फरार हो गई थी। इसके बाद बैंक द्वारा पांच दिनों तक की गई आंतरिक जांच में 41.58 लाख रुपये के गबन का खुलासा हुआ। मामले में 29 मई को जैतापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

ऑनलाइन गेमिंग और हवाई यात्राओं में उड़ाई रकम

थाना प्रभारी के अनुसार, बैंक की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि गबन की पूरी राशि रितु गोयल ने हड़पी थी। जांच में शाखा प्रबंधक राजेश राठौर तथा बैंक कर्मचारी त्र्यंबक वाणी की भी प्रकरण में संलिप्तता पाई गई, जिसके आधार पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रितु गोयल ने गबन की अधिकांश राशि ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर दी, जबकि शेष रकम अपने परिवार के साथ हवाई यात्राओं और होटलों में ठहरने पर खर्च की।

30 दिन गंभीर प्रदूषित रहा सतना, अब शून्य पर आया

पीथमपुर में हर 11वें दिन हवा रही खतरनाक, भोपाल की हालत भी ठीक नहीं

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के शहरों की हवा में तीन साल के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। संसद में पेश 2023 से 2025 के वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) आंकड़ों के अनुसार, सतना ने गंभीर प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 30 से घटाकर शून्य कर दी, जबकि पीथमपुर में 2025 के दौरान 33 दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही, यानी लगभग हर 11वें दिन लोगों को खतरनाक हवा में सांस लेनी पड़ी। राजधानी भोपाल में भी सुधार तो हुआ, लेकिन 2025 में यहां अब भी 8 दिन गंभीर प्रदूषण दर्ज हुआ। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के कुछ शहर तेजी से सुधरे हैं, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।

सतना ने कैसे बदली अपनी तस्वीर?- तीन साल पहले यानी 2023 में सतना में 30 दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही थी। इसके बाद 2024 और 2025 में यह संख्या शून्य हो गई। यानी लगातार दो वर्षों तक शहर में एक भी सीवियर पॉल्यूशन डे दर्ज नहीं हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सुधार माना जा सकता है।

पीथमपुर सबसे बड़ी चिंता- औद्योगिक शहर पीथमपुर में 2023 में 19, 2024 में 31 और 2025 में 33 गंभीर प्रदूषण वाले दिन दर्ज हुए। इसका अर्थ है कि 2025 में लगभग हर 11वें दिन हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। उपलब्ध एमपी शहरों के आंकड़ों में यह सबसे खराब स्थिति है।

भोपाल में राहत, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं

राजधानी भोपाल में 2023 में 36 और 2024 में 40 गंभीर प्रदूषण वाले दिन दर्ज हुए थे। 2025 में यह संख्या घटकर 8 रह गई। यानी सुधार स्पष्ट है, लेकिन राजधानी अब भी गंभीर प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चला रही सरकार

लोकसभा में सोमवार को वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सवाल के जवाब में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत किए गए प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है। सरकार के अनुसार, देश के 24 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 130 गैर-अनुपालक (नॉन-अटेनमेंट) शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 16,423.56 करोड़ रुपए की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।इसके परिणामस्वरूप 108 शहरों में वर्ष 2017-18 की तुलना में 2025-26 में पीएम-10 की सांद्रता घटी है। इनमें 72 शहरों में 20 प्रतिशत से अधिक तथा 26 शहरों में 40 प्रतिशत से अधिक कमी दर्ज की गई है।

उद्योगों और वाहनों पर ऐसे रखी जा रही निगरानी

सरकार ने बताया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम-1981 तथा जल अधिनियम-1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां उद्योगों को संचालित करने की अनुमति एवं निगरानी करती हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2006 के तहत कई उद्योगों के लिए पर्यावरण स्वीकृति और नियमित अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य है। सरकार ने 17 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) अनिवार्य कर दी है। इससे प्रदूषण के आंकड़े सीधे केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक पहुंचते हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई की जाती है।

भोपाल में बादल, मुरैना में तेज पानी गिरा

इंदौर-उज्जैन समेत 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट; मप्र में अब तक 13.2 इंच बारिश

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में ट्रफ समेत दो मानसूनी सिस्टम एक्टिव हैं। भोपाल में सुबह से कभी धूप, कभी बादल की स्थिति बनी हुई है। मुरैना में तेज पानी गिरा। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों- सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल में भारी बारिश यानी हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में 4 इंच या इससे ज्यादा पानी गिर सकता है।

वहीं, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश

हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अब तक प्रदेश में औसत 13.2 इंच (336.7 मिमी) बारिश हुई है जबकि 16 इंच (407 मिमी) पानी गिर जाना था। इस तरह 2.8 इंच यानी 17 प्रतिशत बारिश कम हुई है। दूसरी ओर, पूर्वी हिस्से में 20 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 15 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

इन 47 जिलों में औसत से कम बारिश- अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मऊगंज, नरसिंहपुर, निवाड़ी, पांढुर्णा, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, आगर-मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, रतलाम, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा।

वहीं, 8 जिले- भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, मंदसौर, राजगढ़ और सीहोर में औसत से ज्यादा पानी गिर चुका है। देवास में 29 प्रतिशत बारिश ज्यादा हुई है।

नए सिस्टम का असर 28 से 30 जुलाई तक- मौसम एक्सपर्ट शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब अब पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा तट के बेहद करीब पहुंच चुका है। आज से यह आगे बढ़ेगा। यह सिस्टम झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से 28 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश में अति भारी या भारी बारिश हो सकती है।

महाकाल मंदिर अन्नक्षेत्र में दक्षिण भारतीय प्रसाद मिलना शुरू

हर मंगलवार और शुक्रवार श्रद्धालुओं को परोसे जाएंगे इडली-सांभर, पोंगल और पायसम

उज्जैन (नप्र)। मध्यप्रदेश में पहली बार किसी मंदिर के निःशुल्क अन्नक्षेत्र में श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे जाएंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से श्री महाकालेश्वर मंदिर के निःशुल्क अन्नक्षेत्र में की गई। अब प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय पारंपरिक व्यंजन प्रसाद के रूप में परोसे जाएंगे।

अब तक अन्नक्षेत्र में श्रद्धालुओं को दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मिठाई परोसी जाती थी। अब मंदिर समिति ने देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विविधता में एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारतीय भोजन को भी शामिल किया है। मंगलवार को श्रद्धालुओं को सांभर, इडली, स्टीम राइस, मौसमी सब्जी और पोंगल परोसा जाएगा, जबकि शुक्रवार को पुलिहोरा, पायसम, रसम, स्टीम राइस और मौसमी सब्जी प्रसाद के रूप में दी जाएगी।

एक भारत, अनेक परम्पराएं की भावना से शुरुआत

महाकाल मंदिर समिति की उप प्रशासक सिम्मी यादव ने बताया कि निःशुल्क अन्नक्षेत्र में दक्षिण भारतीय पारंपरिक प्रसाद की शुरुआत रस संगमम् - विभिन्न स्वादों, व्यंजनों एवं संस्कृतियों का मिलन और एक भारत, अनेक परम्पराएं की भावना के साथ की गई है। इसका उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी संस्कृति और स्वाद से जोड़ना है। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि दक्षिण भारतीय व्यंजनों की यह व्यवस्था अब प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से रहेगी। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इडली, सांभर, सब्जी और स्टीम राइस का प्रसाद ग्रहण किया और भोजन की गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की।

छत टपकती है, दीवारों में दरारें हैं..

धार के जर्जर स्कूल में 400 छात्र रोज जोखिम के बीच पढ़ने को मजबूर, जिम्मेदारों से मरम्मत की उम्मीद

धार (नप्र)। धार जिले के दिग्ठान स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जर्जर हालत ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक के करीब 400 छात्र असुरक्षित माहौल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और सुविधाजनक शिक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

विद्यालय भवन की दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। कई जगहों पर प्लास्टर उखड़ गया है और सरिए तक दिखाई देने लगे हैं। वहीं टीन की छत में बड़े-बड़े छेद होने के कारण बारिश के दौरान पानी सीधे कक्षाओं में गिरता है।

बारिश में भीग जाती हैं किताबें-कॉपियां, पढ़ाई होती है प्रभावित- छत से पानी टपकने के कारण छात्रों की किताबें और कॉपियां भीग जाती हैं। बारिश के दिनों में कक्षाओं में बैठना मुश्किल हो जाता है। छात्र हर दिन डर के साए में पढ़ाई करते हैं और उन्हें हमेशा छत या दीवार गिरने का खतरा बना रहता है। छात्रों का कहना है कि पुराने भवन की मरम्मत नहीं होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

पेयजल और शौचालय की सुविधा भी नहीं

विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। छात्रों के लिए पूरे दिन की जरूरत का पानी केवल एक ड्रम में भरकर रखा जाता है, जिसकी नियमित सफाई भी नहीं होती। इसके अलावा स्कूल परिसर में बाउंड्रीवाल नहीं होने से सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बना रहता है। परिसर में झाड़ियों के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है।

इसी परिसर में संचालित प्राथमिक विद्यालय का भवन भी जर्जर स्थिति में है। भवन खराब होने के कारण पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। इससे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

छात्र ने बताया- दीवार गिरने के बाद भी नहीं हुआ सुधार

11वीं कक्षा के छात्र हर्षवर्धन राठौर ने बताया कि स्कूल काफी पुराना है। एक बार स्कूल की दीवार भी गिर चुकी है, जिसके बाद से छात्रों में हमेशा डर बना रहता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में पीने के पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही परिसर में फैली झाड़ियों के कारण मच्छरों और बीमारी का खतरा भी बना रहता है।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

रिटायर्ड लोगों के भरोसे छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड

छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड राज्य का कमाऊ उपक्रम है और जनता से सीधा वास्ता रखने वाला भी। सरकार ने इस बोर्ड को रिटायर्ड लोगों के हवाले कर दिया है। छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड के अधीन तीन कंपनियां हैं, तीनों ही कंपनियों के प्रबंध संचालक सेवावृद्धि पर चल रहे हैं। कहते हैं इनको एक बार-दो बार सेवावृद्धि नहीं मिली, बल्कि तीन-चार बार सेवावृद्धि मिल चुकी है। ऐसा लग रहा है बिजली बोर्ड में कंपनी के एमडी बनने लायक अफसर ही नहीं हैं। बताते हैं जेनरेशन कंपनी के एमडी संजीव कुमार कटियार चौथी बार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें दो बार एक्सटेंशन मिल चुका है। बिजली बोर्ड में रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है। बताते हैं संजीव कुमार कटियार साहब कांग्रेस के जमाने से इस पद पर जमे हुए हैं। वे भूपेश बघेल की सरकार में भी एक बार एक्सटेंशन ले चुके हैं और विष्णुदेव साय की सरकार में भी बल्ले-बल्ले है। ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी राजेश कुमार शुक्ला भी रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी मेहमान बने हुए हैं। कहते हैं शुक्ला साहब सेवावृद्धि पर चल रहे थे और रिटायरमेंट की उम्र को छूने के बाद फिर कृपा बरस गई। वितरण कंपनी के एमडी भीमसिंह कंवर पर भी सरकार मेहरबान है। खबर है कि भीमसिंह को तीसरी बार एक्सटेंशन मिला हुआ है। बिजली बोर्ड का घाटा पूरा करने के लिए सरकार एक तरफ बिजली की दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल रही है। दूसरी तरफ नए खून को मौका देने की जगह पुराने लोगों से गाड़ी खींच रही है।

महिला पार्षद की ऊँची उड़ान

कहते हैं भाजपा की एक महिला पार्षद रायपुर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और उनके आसपास रहने वाले लोगों के सामने खुले तौर पर इच्छा जाहिर कर दी है। भाजपा की आंधी में रायपुर नगर निगम की पार्षद बनी महिला नेत्री की वार्ड चुनाव में हवाई लैंडिग हुई। छत्तीसगढ़ भाजपा के एक कर्णधार की कृपा से चुनाव से टिकट मिल गया और किस्मत ने साथ दिया और चुनाव जीत गई। जबकि उस वार्ड से चुनाव लड़ने के भाजपा के एक कार्यकर्ता सालों से मेहनत कर रहा था। चर्चा है कि एक भाजपा विधायक ने महिला पार्षद को हवा में नहीं उड़ने की सलाह दी और जमीन में रहने की नसीहत दी। बताते हैं विधायक जी ने महिला पार्षद से कहा-सालों के संघर्ष के बाद पार्टी की उन पर कृपा हुई। विधायक जी द्वारा महिला पार्षद को दी गई नसीहत पार्टी के भीतर खूब चर्चा में है। कहा जाता है वार्ड में महिला पार्षद के होर्डिंग्स और पोस्टर ही नजर आते हैं, वह कभी नजर नहीं आती। अब महिला पार्षद मैडम की अपने ही वार्ड में जमीन खिसकती नजर आ रही है, पर वे हैं कि विधानसभा के लिए गोते लगाना शुरू कर दी हैं।

पीए के भरोसे मंत्री जी

कहते हैं छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी अपने पीए पर इतना निर्भर हो गए हैं कि उसकी सलाह के बिना एकदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। पीए साहब एक निगम से प्रतिनियुक्ति पर मंत्री जी के स्टाफ में शामिल हुए हैं। बताते हैं पीए साहब बहुत ही कम समय में मंत्री जी के विश्वासपात्र बन गए। सर्वगुणसंपन्न पीए साहब अब मंत्री जी के आंख-कान बने हुए हैं। सुनने में आता है कि पीए बड़ा कलाकार है। मंत्री जी के नाम पर अपना उल्लू सीधा तो करता ही है। वह मंत्री जी को उलटा-सीधा पाठ भी पढ़ाता है। वैसे मंत्रिमंडल में फेरबदल की अफवाह के बीच मंत्री जी को हटाए जाने की चर्चा चल पड़ती है। पर अभी तो पीए साहब मंत्री जी की लाठी बने हुए हैं।

तंगी में प्राइवेट अस्पताल मालिक

चर्चा है हाल ही में बड़े तामझाम के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी में खोले गए एक प्राइवेट अस्पताल मालिक का भूत उतर गया है। कहते हैं कि अस्पताल मालिक जिस उम्मीद के साथ अस्पताल खोले थे,वह उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहा है। भारी प्रचार-प्रसार के बाद भी अस्पताल में मरीज कम ही आ रहे हैं। इस कारण अस्पताल की आर्थिक स्थिति पटरी से उतरने लगी है और उसके मालिक को बाजार से धन उधार में लेना पड़ रहा है। इस अस्पताल में कुछ ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं के पैसे लगे हैं। अब देखते हैं अस्पताल चलाने के लिए मालिक को बाजार से कितना धन मिल पाता है और उधार के धन से कितने दिन गाड़ी चलती है।

सचिव के नाम उगाही

चर्चा है कि एक निर्माण विभाग के सचिव के नाम से राज्य में उगाही का खेल चल रहा है। कहते हैं सचिव के परिचित या दोस्त बताकर कुछ लोग निर्माण विभाग के अफसरों के दफ्तर में जाकर धौंस जमाते हैं। वे कहते हैं सचिव साहब ने भेजा है। अब किसी अफसर की हिम्मत नहीं कि सचिव महोदय से बात कर उसकी पुष्टि कर लें। कुछ दमदार अफसर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, पर कुछ उनकी झोली भर देते हैं। यह खेल आदिवासी और मैदानी इलाकों में चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि सरगुजा के अंदरूनी इलाकों में वसूलीबाज ज्यादा सक्रिय हैं। अब सचिव महोदय तक उनके नाम के दुरुपयोग की खबर किसी साहसी अधिकारी ने पहुंचाई या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया है।

छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों में जगा जोश

चर्चा है कि नीट पेपरलीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सक्रियता के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं में जोश जग गया। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरने के बाद राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद राज्य के नेता सड़क पर आ गए। नीट पेपरलीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए ब्लाक स्तर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों के एक्शन के खिलाफ भाजपा ने राजीव भवन का घेराव कर दिया। इससे राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। भाजपा के एक्शन के खिलाफ और कांग्रेस के लोगों से मारपीट का आरोप लगाते कांग्रेसी राजधानी के खम्हारडीह थाने में तकरीबन 19 घंटे जम गए। राहुल गाँधी से इंस्पायर होकर राज्य के कांग्रेसी नेता भी बांहे फड़का रहे हैं। अब देखते हैं यह जोश कितने दिन बना रहता है और राज्य की भाजपा सरकार को कितना हिला पाते हैं।

मंत्रिमंडल में फेरबदल ठंडे बस्ते में ?

नीट पेपरलीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या विष्णुदेव साय मंत्रिमडल में फेरबदल अब लंबे समय के लिए टल गया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता अब नीट पेपरलीक मामले में हुए नुकसान की भरपाई करना है। पहले केंद्र सरकार में बदलाव होगा, फिर राज्यों की तरफ नजर दौड़ाई जाएगी, कहा जा रहा है तब तक के लिए छत्तीसगढ़ सुरक्षित जोन में चला गया। नीट पेपरलीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से साफ़ है कि मोदी सरकार छात्रों के सामने झुकी। कहा जा रहा है फेरबदल की संभावना से शंकाओं से घिरे छत्तीसगढ़ के कुछ मंत्री अब कुछ दिन चैन की नींद लेंगे।

महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व

अलंकरण समारोह

नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

29 जुलाई, 2026 । गीता भवन
माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

गुरु पूर्णिमा

के पावन अवसर पर
श्रद्धेय गुरुजनों को नमन

सांदीपनि विद्यालय

चरण-I एवं II

8.48 लाख+
विद्यार्थी क्षमता

773 विद्यालय | **₹24,915** करोड़ का निवेश

शिक्षा का आधुनिक सुदृढ़ीकरण

सांदीपनि विद्यालयों में-
नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

विश्व स्तरीय अधोसंरचना-
सर्वसुविधायुक्त डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक लैब, कंप्यूटर एवं समृद्ध पुस्तकालय

निःशुल्क और सुरक्षित बस सुविधा-
CCTV निगरानी, प्रशिक्षित स्टाफ के साथ

समग्र व्यक्तित्व विकास-
व्यावहारिक कौशल, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता पर विशेष फोकस

बेहतर परीक्षा परिणाम-
10वीं कक्षा का परिणाम 68 से बढ़कर हुआ 88 प्रतिशत, वर्ष 2026 में 10वीं के 41 विद्यार्थी, 12वीं के 17 विद्यार्थी मेरिट में

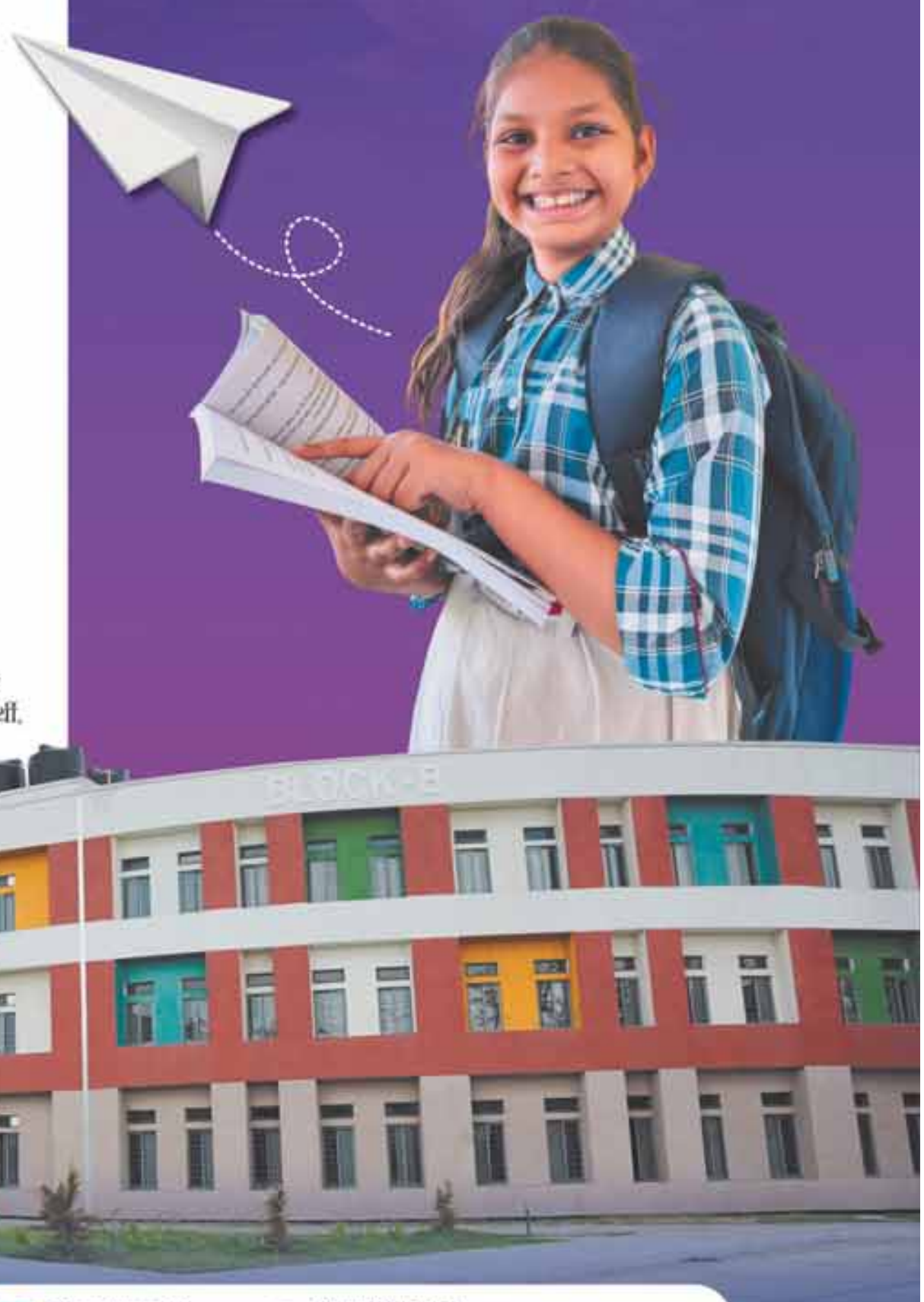

सीधा प्रसारण webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhypradesh @jansamparkMP JansamparkMP

D-11066/26

जनसम्पर्क द्वारा जारी